सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 98, नई दिल्ली, मंगलवार 17 जून 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

सहनशील होना अच्छी बात है... पर अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है...!!!

03 दिल्ली भाजपा कार्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी

06 जब पढ़ाई में न लगे मन....

08 चाईबासा में तालाब चोरी !1964 के बाद गायब तालाबों को ढूंढिए : चंदन कुमार ,

परिवहन विशेष के मुख्य संपादक और टोलवा ट्रस्ट की महासचिव आज पहुंचेंगे झारखंड (रांची)

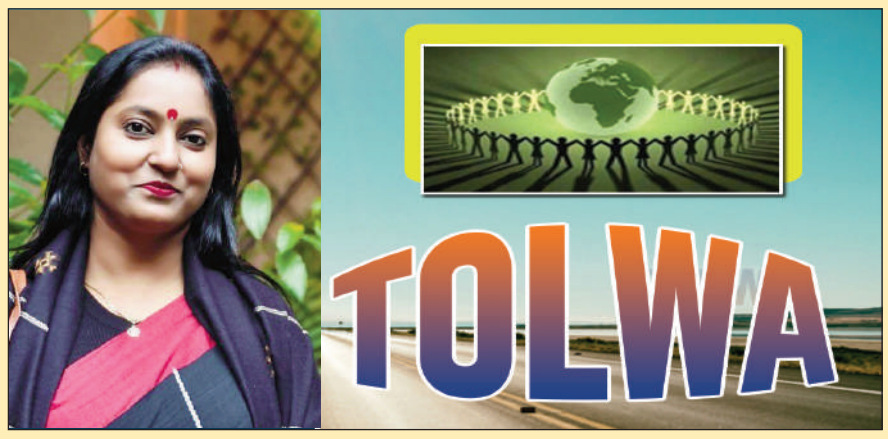

संजय बाटला

नई दिल्ली। परिवहन विशेष हिंदी दैनिक समाचार पत्र का कार्यालय झारखंड में खोलने और झारखण्ड में कार्यरत संवादाताओं से मुलाकात कर वहां के बारे मे जायजा लेंगे और साथ ही टोलवा ट्रस्ट द्वारा वहां आने वाले समय में शुरू करें जाने वाले हॉस्पिटल के प्रॉजेक्ट की जानकारी प्राप्त करेंगे। हॉस्पिटल से संबंधित सभी तथ्यों की जानकारी हेतु टोलवा ट्रस्ट की महासचिव भी दिल्ली से रांची पहुंच रही हैं।

महासचिव ने बताया की राची से कुछ दुरी पर टेम्पल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट (टोलवा ट्रस्ट) 28 एकड़ में वहां की जनता को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्यों से (आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस) के समान हॉस्पिटल खोलने की झारखंड सरकार से अनुमति प्राप्त कर के जल्दी ही श्रीगणेश करेगी। उनका कहना है की इस हॉस्पिटल के खुलने से ना सिर्फ झारखंड की जनता अपितु बिहार और बंगाल की जनता को भी फायदा पहुंचेगा और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा फ्री प्राप्त होगी।

परिवहन विशेष मुख्य संपादक महासचिव के साथ उस जगह का दौरा भी करेंगे जहां हॉस्पिटल खुल रहा है।

संपादक द्वारा बताया गया की टोलवा ट्रस्ट के इस कार्य को पूरा करने के लिए विशेष न्यूज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और परिवहन विशेष समाचार पत्र से जो भी मदद होगी वह करेंगे क्योंकि यह एक सामाजिक हित का अच्छा प्रोजेक्ट है।

नितिन गडकरी 19जून को रांची में एलिवेटेड कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। झारखंड की राजधानी में आगामी 19जून को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं. इसके शुरू हो जाने से रांची वासियों को रातू रोड में लगने वाली ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी.कभी रातू रोड में नागाबाबा खटाल से पिस्का मोड़ तक करीब 2.5 किमी का सफर पूरा करने में आधा से एक घंटा का समय लगता था. लेकिन एलिवेटेड कॉरिडोर के जरिये अब यह सफर महज सात मिनट में पूरा हो पायेगा. इस 3.57 किमी लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने में करीब 400 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं. रातू रोड फ्लाईओवर (एलिवेटेड कॉरिडोर) का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा कराया गया है. वहीं, संवेदक के रूप में केसीसी बिल्डकॉन ने निर्माण कार्य पूरा किया है. इसके निर्माण में 400 करोड़ रुपये की लागत (जमीन अधिग्रहण व शिफ्टिंग समेत) आयी है. यह फ्लाईओवर कुल 101 पिलरों पर खड़ा है. इसमें नागाबाबा खटाल से हेहल पोस्ट ऑफिस तक कॉरिडोर के कुल 37 पिलर हैं. वहीं, पिस्का मोड़ से इटकी रोड में 300 मीटर आगे तक कुल 14 पिलर हैं, निर्माण में कुल 102 स्लैब का उपयोग किया गया है. यद्यपि इसे अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है. सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर इस एलिवेटेड कॉरिडोर के उद्घाटन का आग्रह किया था. सांसद के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने 19 जून को रांची आकर उद्घाटन करने पर सहमति दी .

दिल्ली मेट्रो ने फेज चार में हासिल की खास उपलब्धि, डबल डेकर की तरह तैयार हुआ सबसे ऊंचा स्टेशन

दिल्ली मेट्रो ने येलो लाइन के हैदरपुर बादली मोड़ स्टेशन पर एक अनूठा डबल डेकर एलिवेटेड स्टेशन बनाया है। जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर का यह स्टेशन पुराने स्टेशन के ऊपर बना है। इससे यात्रियों को इंटरचेंज में सुविधा होगी और संसाधनों की भी बचत हुई है। यह स्टेशन 23 .58 मीटर ऊंचा है जो सात मंजिला इमारत के बराबर है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ढांचागत निर्माण में कई कीर्तिमान गढ़ चुकी दिल्ली मेट्रो ने फेज चार में भी एक खास उपलब्धि हासिल की है। इस बार येलो लाइन के हैदरपुर बादली मोड़ एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन के प्लेटफार्म के ऊपर फेज चार में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर का नया स्टेशन तैयार किया गया है। 29.262 किलोमीटर लंबी जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर मजेंटा लाइन (बोटेनिकल गार्डन-जनकपुरी पश्चिम) कॉरिडोर की विस्तार परियोजना है।

इस वर्ष के अंत तक इस कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू होने पर हैदरपुर बादली मोड़ एलिवेटेड स्टेशन के पहले तल के प्लेटफार्म से येलो लाइन की मेट्रो और इसके ऊपर बने स्टेशन के प्लेटफार्म से मजेंटा लाइन की मेट्रो चलती नजर आएगी।

दिल्ली मेट्रो का पहला एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का कहना है कि यह दिल्ली मेट्रो का पहला एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन है, जहां पुराने स्टेशन के प्लेटफार्म के ऊपर नए कॉरिडोर का स्टेशन बना है। नए कॉरिडोर के स्टेशन के फिनिशिंग का काम चल रहा है। मौजूदा समय में हैदरपुर बादली मोड़ स्टेशन से येलो लाइन की मेट्रो का परिचालन होता है। फेज तीन में येलो लाइन का यह स्टेशन बना था।

फेज चार में यह मजेंटा लाइन के साथ इंजरचेंज स्टेशन होगा। पहले से ही चालू स्टेशन का विस्तार करना मुश्किल होता है। इस वजह से दो कॉरिडोर के इंटरचेंज स्टेशनों के बीच लंबे सब-वे या फुटओवर ब्रिज बनाने पड़ते हैं। पहले से मौजूद स्टेशन के एक या दो गेट भी निर्माण कार्य के लिए बंद करने पड़ते हैं।

डीएमआरसी ने हैदरपुर बादली मोड़ में फेज चार का इंटरचेंज स्टेशन बनाने की तैयारी फेज तीन का स्टेशन बनाने के दौरान की कर ली थी। इसलिए फेज तीन के स्टेशन के निर्माण के दौरान ही फेज चार के कॉरिडोर को ध्यान में रखकर येलो लाइन के प्लेटफार्म के ऊपर नए प्लेटफार्म का ढांचा व सीढ़ियां तैयार कर ली गई थीं।

लिफ्ट व एस्केलेटर लिए जगह सुनिश्चित कर ली गई

लिफ्ट व एस्केलेटर लिए जगह सुनिश्चित कर ली गई थी। साथ ही नींव भी इतनी मजबूत बनाई गई थी कि नए कॉरिडोर के मेट्रो परिचालन की भार झेल सके। तब फेज चार के कॉरिडोर के स्टेशन की छत व तकनीकी कार्य नहीं किए गए थे। फेज चार का कार्य शुरू होने के बाद नए कॉरिडोर के स्टेशन की छत, मेट्रो ट्रैक, ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन, मेट्रो परिचालन से जुड़े उपकरण लगाए गए। इससे अब यह दो मेट्रो कॉरिडोर के डबल डेकर स्टेशन की तरह दिखने लगा है। यह पहले की गई तैयारी से ही संभव हो सका। देश किसी परियोजना में पहले ऐसा नहीं हुआ।

संसाधन की हुई बचत

डीएमआरसी के अनुसार एक एलिवेटेड स्टेशन के निर्माण में कई वर्ष समय लग जाता है और सैकड़ों कर्मचारी तैनात करने पड़ते हैं। इस स्टेशन का बुनियादी ढांचा पहले से उपलब्ध होने से नए कॉरिडोर का इंटरचेंज स्टेशन तैयार करने में समय व संसाधन की बचत हुई। साथ ही यात्रियों को एक करिडोर से दूसरे कॉरिडोर की मेट्रो बदलने में आसानी होगी।

सात मंजिला भवन के बराबर ऊंचा है यह स्टेशन

हैदरपुर बादली मोड़ स्टेशन पर फेज चार का स्टेशन 23.58 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जो सात मंजिला भवन की ऊंचाई के बराबर है। यह दिल्ली मेट्रो का सबसे ऊंचा मेट्रो स्टेशन है। इस स्टेशन के नजदीक ही पिलर संख्या 340 के पास जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर का वायाडक्ट 28.362 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जो दिल्ली मेट्रो का सबसे ऊंचा प्वाइंट है। पहले धौला कुआं में पिंक लाइन का कॉरिडोर सबसे ऊंचा था, जिसका वायाडक्ट 23.6 मीटर ऊंचा है।

स्वच्छता पखवाड़ा: आइए मिलकर करें अपने पार्क और समाज का कायाकल्प

डॉ. अंकुर शरण के द्वारा

जब बात अपने देश, समाज या पर्यावरण की होती है, तो जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि हम सबकी होती है। स्वच्छता पखवाड़ा इसी जिम्मेदारी को समझने और निभाने का एक सुनहरा अवसर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ सरकार या नगरपालिका ही इस परिवर्तन की वाहक बनेगी? या हम स्वयं अपने आस-पास की सफाई और सुंदरता के लिए आगे आएंगे?

PHE एजुकेशन ट्रस्ट ने पर्यावरण पाठशाला (Indian Green Buddy) के साथ मिलकर एक संयुक्त पहल शुरू की है – जिसमें प्रत्येक नागरिक को प्रेरित किया जा रहा है कि वह अपने पार्क, गली, मोहल्ले और समाज की सफाई की जिम्मेदारी खुद उठाए।

इस अभियान की शुरुआत फरीदाबाद में की गई, जहाँ स्थानीय सक्रिय URWA सदस्यों ने Springfield पार्क और इसके आस-पास के सेक्टरों में स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान प्लास्टिक की बोतलें, रैपर, कचरे के ढेर और अन्य अपशिष्ट बड़ी मात्रा में इकट्ठे किए गए।

क्यों है यह आंदोलन ज़रूरी?

पार्क केवल हरियाली का प्रतीक नहीं, सामुदायिक जीवन का केंद्र भी हैं।

बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की सैर, महिलाओं की चहल-पहल – सब यहीं से जुड़ी होती है।

लिटरिंग और प्लास्टिक कचरा न केवल सौंदर्य को बिगाड़ता है, बल्कि स्वास्थ्य पर भी असर डालता है।

गंदगी बीमारियों को जन्म देती है और वातावरण को दूषित करती है।

पर्यावरण पाठशाला

एक साफ पार्क एक स्वस्थ समाज की पहचान है।

यदि हम बदलाव देखना चाहते हैं, तो शुरुआत अपने घर, गली और पार्क से करनी होगी।

इस आंदोलन को और विस्तार देते हुए Global Confederation of NGOs के साथ साझेदारी कर अन्य पार्कों और क्षेत्रों में भी यह पहल शुरू की गई है। यह केवल सफाई का नहीं, एक मानसिकता परिवर्तन का अभियान है – 'मैं करूंगा बदलाव की शुरुआत'।

कैसे जुड़ सकते हैं आप?

सप्ताह में एक दिन पार्क या समाज की सफाई के लिए समय निकालिए।

कचरा ना फैलाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें।

अपने बच्चों को स्वच्छता के संस्कार सिखाइए।

सोशल मीडिया पर सफाई अभियान की तस्वीरें और कहानियां साझा कर जागरूकता फैलाइए।

पर्यावरण पाठशाला से जुड़ कर स्थानीय टीम का हिस्सा बनें। Send email at indiangreenbuddy@gmail.com

परिवर्तन हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब हम अपने घर, गली या पार्क की ज़िम्मेदारी स्वयं उठाते हैं, तब एक नए समाज की नींव रखी जाती है – साफ, स्वस्थ और जागरूक।

आइए इस स्वच्छता पखवाड़ा को एक जनांदोलन बनाएं। यह सिर्फ एक सफाई अभियान नहीं, बल्कि एक संस्कार है।

जहाँ देखो गंदगी, वहीं उठाओ झाड़ू। स्वच्छ भारत का सपना, हम सब मिलकर साकार करें।

– डॉ. अंकुर शरण, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरण प्रेरक

PHE Education Trust & Paryavaran Paathshala

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई

किसने की महामृत्युंजय मंत्र की रचना और जाने इसकी शक्ति...

शिवजी के अनन्य भक्त मृकण्ड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे, विधाता ने उन्हें संतान योग नहीं दिया था।

मृकण्ड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं. इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्नकर यह विधान बदलवाया जाए।

मृकण्ड ने घोर तप किया, भोलेनाथ मृकण्ड के तप का कारण जानते थे इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन न दिया लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोले झुक ही जाते हैं।

महादेव प्रसन्न हुए, उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूं लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ विषाद भी होगा..।

भोलेनाथ के वरदान से मृकण्ड को पुत्र हुआ जिसका नाम मार्कण्डेय पड़ा. ज्योतिषियों ने मृकण्ड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष है।

ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया. मृकण्ड ने अपनी पत्नी को आश्वत किया- जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोले इसकी रक्षा करेंगे. भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है।

मार्कण्डेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिवमंत्र की दीक्षा दी. मार्कण्डेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी. उन्होंने मार्कण्डेय को अल्पायु होने की बात बता दी।

मार्कण्डेय ने निश्चय किया कि माता-पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया है. बारह वर्ष पूरे होने को आए थे।

मार्कण्डेय ने शिवजी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे।

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्-मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए. यमदूतों ने देखा कि बालक महाकाल की आराधना कर रहा है तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की. मार्केण्डेय ने अखंड जप का संकल्प लिया था।

यमदूतों का मार्केण्डेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए. उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए।

इस पर यमराज ने कहा कि मृकण्ड के पुत्र को मैं स्वयं लेकर आऊंगा. यमराज मार्कण्डेय के पास पहुंच गए।

बालक मार्कण्डेय ने यमराज को देखा तो जोर-जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया

यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की तभी जोरदार हुंकार से मंदिर कांपने लगा. एक प्रचण्ड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गईं।

शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए. उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया?

यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे. उन्होंने कहा- प्रभु मैं आप का सेवक हूं. आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है।

भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले- मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूं और मैंने इसे दीर्घायु होने का वरदान दिया है. तुम इसे नहीं ले जा सकते।

यम ने कहा- प्रभु आपकी आज्ञा सर्वोपरि है. मैं आपके भक्त मार्कण्डेय द्वारा रचित महामृत्युंजय का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा।

महाकाल की कृपा से मार्केण्डेय दीर्घायु हो गए. उवके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है।

कोलेस्ट्रॉल

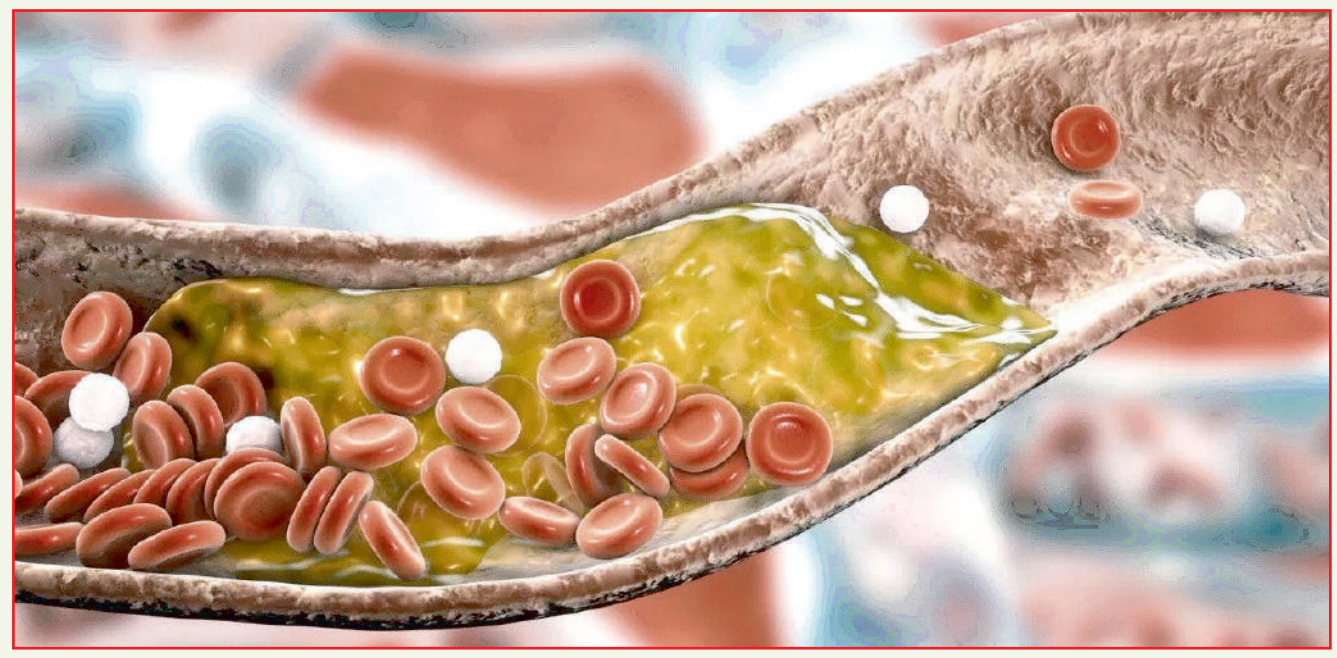

हमारा हृदय कई कार्यों को करने के लिए जाना जाता है। हृदय को स्वस्थ रखने और हृदय रोगों के जोखिम से दूरी बनाने के लिए कई कारकों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हीं में से एक है कोलेस्ट्रॉल (Cholestrol), जिसके स्तर को नियंत्रित करना बेहद आवश्यक है। इसे नियंत्रित करने के लिए स्वस्थ जीवनशैली के साथ-साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने के उपाय भी कारगर साबित हो सकते हैं।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर देता है ये संकेत, समय पर पहचान लें वरना जान से हाथ धोना पड़ सकता है आज की आलस भरी लाइफस्टाइल, अनहेल्थी फूड और स्मोकिंग-ड्रिंक जैसी आदतों के चलते युवाओं में भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखी जा रही है। बॉडी में यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए तो हार्ट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है।

शरीर में पाया जाने वाला कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है। ये लीवर से बनता है। कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार के होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जमकर बीमारियां पैदा करता है।

यदि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अधिक बढ़ने से पहले सही इलाज लिया जाए तो इसके नुकसान को टाला जा सकता है। जब शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हमारी बॉडी कई संकेत देती है। आप इन संकेतों को पहचान कर अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा सकते हैं। फिर डॉक्टर से इलाज लेकर इसे कंट्रोल में रख सकते हैं।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के संकेत

1 पैरों का सुन्न पड़ना

कभी-कभी आप ने देखा होगा कि हमारे पैर अचानक सुन्न पड़ जाते हैं। ऐसा हाई कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) के चलते होता है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से नसों में ब्लॉकेज हो जाता है। इससे खून की सप्लाई कम हो जाती है या पूरी तरह रुक जाती है।

2 दिल का दौरा पड़ना

कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होने से आर्टरीज में ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाता है। यह स्थिति हार्ट अटैक (Heart Attack) लाती है। इसलिए अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखना दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है।

3.हाई ब्लड प्रेशर

कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने से शरीर का उच्च रक्त चाप यानि High Blood Pressure भी बढ़ता है। इसलिए आप बीपी मशीन से हर महीने या 15 दिन में ब्लड प्रेशर मापते रहे। इससे आपको कोलेस्ट्रॉल के खतरे का संकेत मिल जाएगा।

4 *नाखून का रंग बदलना*

आपके नाखूनों का कलर चेंज होना भी हाई कोलेस्ट्रॉल का एक संकेत होता है। दरअसल ब्लड में बैड कॉलेस्ट्रॉल के अधिक बढ़ने से धमनियां ब्लॉक होने लगती है। इसमें खून की सप्लाई कम हो तो आपके गुलाबी नाखून पीले दिखने लगते हैं।

5 *बेचैनी*

सांस लेने में तकलीफ होना, जी मिचलाना, थकावट, सीने में दर्द बढ़ना, बेचैनी होना भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की निशानी है। ये लक्षण दिखने पर तुरंत आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना चाहिए।

ऐसे रोके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से

कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी डाइट में सैचुरेटेड फैट की जगह अनसैचुरेटेड फैट्स लें। जैसे ऑलिव ऑयल, सूरजमुखी के तेल, नट्स और सीड्स ऑयल जैसी चीजों में हेल्दी फैट पाया जाता है।

इसके अतिरिक्त आप रोज व्यायाम कर भी अपने कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम कर सकते हैं।

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, आप अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल में बदलाव कर सकते हैं.

खान-पान में बदलाव

शाकाहारी भोजन करें. बीन्स, दाल, टोफ़ू, नट्स, फल, सब्ज़ियां, और कम वसा वाले डेयरी उत्पाद खाएं.

सोयाबीन, फ़ाइबर सप्लीमेंट, सेब, अंगूर, सूरजमुखी, और केनोला जैसे वेजिटेबल ऑयल खाएं.

लहसुन, करक्यूमिन, अदरक, काली मिर्च, धनिया, और दालचीनी जैसे मसाले खाएं.

शारीरिक गतिविधियों में बदलाव

नियमित रूप से एक्सरसाइज़ करें.

हफ़्ते में पांच दिन 30 मिनट मॉडरेट फ़िज़िकल एक्टिविटी करें.

हफ़्ते में तीन बार 20 मिनट एरोबिक एक्टिविटी करें.

अन्य बदलाव

धूम्रपान न करें, शराब का सेवन कम करें, वज़न कम करें.

ये लक्षण दिखने पर तुरंत आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना चाहिए एवं डॉ॰ की सलाह ले।

जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता रहता है वह व्यक्ति एक न एक दिन अपने जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है।

सबने देखा होगा कि एक छोटी सी चींटी भी पहाड़ के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती है। कितनी बार वह ऊपर चढ़ती है कितनी बार नीचे गिरती है। फिर भी क्या कभी वह हिम्मत हारती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हारती जिसका परिणाम अंततः यही सामने आता है वह एक दिन पहाड़ पर विजय यात्रा संपन्न करके ही रहती है। तो हम मनुष्य होकर, सर्वसमर्थ होकर भी किसी न किसी को अपनी बैसाखी बनाना चाहतें हैं। और यदि सफल नहीं होते तो किसी दूसरे पर दोषारोपण करने लगें हैं। यह दोषारोपण, अपने भीतर की विक्षिप्तता/असफलता को किसी और के नाम/कंधे जड़ देने का असफल प्रयास भर होता है। आज से अपने आप को इतना सशक्त/शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर दे कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में एक नहीं हजारों समस्याएं भी आ जाए तो भी हम कभी भी अपने कदमों को पीछे हटाने का प्रयास नहीं करेंगें। यदि हम मजबूती के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगें तो अंधकार के बादल अपने आप ही दूर हो जायेंगे। और हमारे आत्मप्रकाश का सूर्य, समस्त भूमंडल को प्रकाशित करना प्रारंभ कर देगा।

कुबेर की साधना कलयुग में तत्काल फलदायी होती है?

क्या है। यह कुबेर के 9 रूप होते है।

1 - उग्र कुबेर -- यह कुबेर धन तो देते ही है साथ में आपके सभी प्रकार के शत्रुओ का भी हनन कर देते है !

2-पुष्प कुबेर --यह धन प्रेम विवाह ,प्रेम में सफलता ,मनो वर प्राप्ति ,स्न्मोहन प्राप्ति ,और सभी प्रकार के दुख से निवृति के लिए की जाती है !

3-चंद्र कुबेर -- इन की साधना धन एवं पुत्र प्राप्ति के लिए की जाती है ,योग्य संतान के लिए चंदर कुबेर की साधना करे !

4-पीत कुबेर -- धन और वाहन सुख संपति आदि की प्राप्ति के लिए पीत कुबेर की साधना की जाती है !इस साधना से मनो वाशित वाहन और संपति की प्राप्ति होती है !

5- हंस कुबेर -- अज्ञात आने वाले दुख और मुकदमो में विजय प्राप्ति के लिए हंस कुबेर की साधना की जाती है !

6- राग कुबेर -- भोतिक और अधियात्मक हर प्रकार की विधा संगीत ललित कलाँ और राग नृत्य आदि में न्पुनता और सभी प्रकार की परीक्षा में सफलता के लिए राग कुबेर की साधना फलदायी सिद्ध होती है !

7-अमृत कुबेर -- हर प्रकार के स्वस्थ लाभ रोग मुक्ति ,धन और जीवन में सभी प्रकार के रोग और दुखो के छुटकारे के लिए अमृत कुबेर की साधना दिव्य और फलदायी है !

8-प्राण कुबेर -- धन है पर कर्ज से मुक्ति नहीं मिल

रही वेयर्थ में धन खर्च हो रहा हो तो प्राण कुबेर हर प्रकार के ऋण से मुक्ति दिलाने में सक्षम है !इन की साधना साधक को सभी प्रकार के ऋण से मुक्ति देती है !

9- धन कुबेर -- सभी प्रकार की कुबेर साधनयों में सर्व श्रेष्ठ है जीवन में हम जो भी कर्म करे उनके फल की प्राप्ति और धन आदि की प्राप्ति के लिए और मनोकामना की पूर्ति हेतु और भाग्य अगर साथ न दे रहा हो तो धन कुबेर की साधना सर्व श्रेष्ठ कही गई है !

21 जून को मनाई जाएगी योगिनी एकादशी, इस दिन करें इन मंत्रों का जाप

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। यह सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती हैं। ऐसे में कुछ लोग निर्जला उपवास भी रखते हैं, जो बेहद कठिन होता है।

सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मुरादें पूरी होती हैं। जुलाई के महीने में योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी पड़ेगी। श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर की निदेशिका ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जगत के नाथ भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन योगिनी एकादशी मनाई जाती है। 21 जून को योगिनी एकादशी है। धर्म शास्त्रों के अनुसार, योगिनी एकादशी व्रत करने से 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित होता है। योगिनी एकादशी पर वैष्णव समाज के लोग व्रत रख विधि-विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि पाने के लिए विशेष उपाय भी करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से एकादशी व्रत करने से जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए।

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। यह सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती हैं। ऐसे में कुछ लोग निर्जला उपवास भी रखते हैं,

जो बेहद कठिन होता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है, उसपर भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। ऐसे में आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार 21 जून के दिन ये व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा-अर्चना करने पर पापों से मुक्ति मिलती हैं।

योगिनी एकादशी

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7.19 बजे शुरू होगी और 22 जून को सुबह 4.28 बजे समाप्त होगी। ऐसे में योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून 2025 को ही रखा जाएगा। वहीं योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को होगा। योगिनी एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून को दोपहर 1.47 बजे से शाम 4.35 बजे के बीच है। पारण तिथि पर हरि वासर समाप्त होने का समय सुबह 9.41 बजे है।

पूजा विधि

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना अधिक शुभ होता है। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी विधि अनुसार पूजा करें और योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। बाद में विष्णु जी की आरती करें। इस दिन आप जरूरतमंद लोगों को भोजन व दान दक्षिणा भी दे सकती हैं, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।

पूजा के दौरान इन मंत्रों का करें जप

विष्णु गायत्री मंत्र

ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात॥

विष्णु मंगल मंत्र

मङ्गलम्भगवान विष्णुः, मङ्गलम्गरुणध्वजः।मङ्गलम्पुण्डरी काक्षः, मङ्गलाय तनो हरिः॥

योगिनी एकादशी व्रत के नियम

ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून, और दाढ़ी कटवाने की भूल न करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है।

मध्य प्रदेश में जरूर करें प्राचीन मंदिर और शक्तिपीठ के दर्शन, महाभारत से जुड़ा है कनेक्शन

अगर आप मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं या फिर यहां जा रहे हैं, तो आप मध्यप्रदेश के शक्तिपीठ मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में तीन शक्तिपीठ हैं। जहां पर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको मध्य प्रदेश के शक्तिपीठों के बारे में बताने जा रहे हैं।

देशभर में कई प्राचीन और फेमस देवी मंदिर हैं, जिनकी महिमा विश्व विख्यात है। माता सती के जिन स्थानों पर अंग गिरे, वहां पर शक्तिपीठ बन गए। भारत में ऐसे 52 शक्तिपीठ हैं। वहीं नवरात्रि के मौके पर लोग मंदिरों या शक्तिपीठ के दर्शन के लिए जाते हैं। अगर आप मध्यप्रदेश के रहने वाले हैं या फिर यहां जा रहे हैं, तो आप मध्यप्रदेश के शक्तिपीठ मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में तीन शक्तिपीठ हैं। जहां पर आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए आपको मध्य प्रदेश के शक्तिपीठों के बारे में बताने जा रहे हैं।

एमपी का प्राचीन शक्तिपीठ

मध्य प्रदेश में आप माता दुर्गा के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहां पर तीन शक्तिपीठों की बहुत मान्यता है और इनको काफी पवित्र माना जाता है। यह तीन शक्तिपीठ हरसिद्धि देवी शक्तिपीठ, शोण नर्मदा शक्तिपीठ और मैहर माता मंदिर है।

हरसिद्धि देवी शक्तिपीठ

मध्य प्रदेश के उज्जैन में हरसिद्धि देवी शक्तिपीठ है। मान्यता है कि यहां पर माता सती की कोहनी गिरी थी। यह मंदिर रुद्र सागर तालाब के पश्चिमी तट पर स्थित है। धार्मिक मान्यता है कि माता दिन में गुजरात और रात में उज्जैन में वास करती हैं।

शोण नर्मदा शक्तिपीठ

मध्य प्रदेश के अमरकंटक में शोण नर्मदा शक्तिपीठ है। यहां पर माता सती का दायां नितंब गिरा था। जिस स्थान पर यह शक्तिपीठ है, वहां पर नर्मदा नदी का उद्गम माना जाता है। जिसकी वजह से भक्त यहां पर देवी मां की नर्मदा स्वरूप में पूजा-अर्चना करते हैं। वहीं शोण नर्मदा शक्तिपीठ को 'शोणाक्षी शक्तिपीठ' के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में मां नर्मदा की मूर्ति पर सुनहरा मुकुट और चांदी का चबूतरा देख सकते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं।

मैहर माता मंदिर

मध्य प्रदेश के सतना जिले में त्रिकुट पहाड़ी पर मैहर माता मंदिर है। नवरात्रि के मौके पर यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जिस स्थान पर माता का मंदिर है, वहां पर मां सती का हार गिरा था। इस मंदिर तक जाने के लिए भक्तों को 1063 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। वहीं मंदिर तक जाने के लिए रोपवे सेवा भी है।

पीतांबरा पीठ

बता दें कि एमपी के दतिया जिले में मां पीतांबरा पीठ स्थित है। यहां पर मां की बगुलामुखी को पीतांबरा के रूप में पूजा की जाती है। नवरात्रि के खास मौके पर यहां पर विशेष रूप से पूजा-अर्चना की जाती है। जिसमें शामिल होने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर में महाभारत काल का धूमावती माता और वनखंडेश्वर महादेव मंदिर भी स्थित है।

दिल्ली भाजपा कार्यालय में लगाई गई प्रदर्शनी

प्रदर्शनी का उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रेखा गुप्ता ने किया

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण के 11 साल पूरे होने पर और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई जिसका उद्घाटन केन्द्रीय मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा एवं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की।

इस मौके पर सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेन्द्र चंदोलिया एवं प्रवीण खंडेलवाल सहित प्रदेश पदाधिकारी, विधायक एवं प्रदर्शनी के संयोजक विधायक अनिल शर्मा भी उपस्थित थे।

इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री सरदार हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली में एक उद्देश्य वाली और दिल्लीवालों की सेवा करने वाली सरकार बनी है। मैं खासकर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि इनके नेतृत्व में 27 सालों के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय के लिए जो माइलस्टोन सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने रखे हैं वह दिल्लीवालों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे।

सरदार हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में जो भी जन कल्याण की योजनाएं चलाई है, उसके बारे में आप सब को पता है। आज की प्रदर्शनी में उन सभी उपलब्धियों को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आज जो अंतरर्राष्ट्रीय स्थिति बनी हुई है, उसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को चौथे स्थान पर पहुंचाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।

उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली ने इलेक्ट्रिक बसों को अपनाया है और उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक के अलावा हम हाइड्रोजन की ओर भी तेजी से बढ़ेंगे। आज दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता सरकार ने कूड़े के पहाड़ के अलावा यमुना की सफाई को तवज्जों दी है इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए अच्छा काम हो रहा है, और आने वाले समय में आप इसका परिणाम देखेंगे।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 11 वर्ष सही मायनों में युग परिवर्तन है। यह 11 साल विश्वास, प्रगति, भरोसे और समाजिक उत्थान के लिए है। इस 11 सालों के स्वर्णिम काल भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में है।

सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 11 साल के अलावा दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के 100 दिन में किए गए कार्यों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। कैसे एक सरकार सिर्फ 100 दिनों में जनता के विश्वास अर्जित करती है और एक भरोसा देती है विकास कार्यों के लिए। हम इस प्रदर्शनी को लेकर प्रत्येक जिला और मंडल में जा रहे हैं ताकि दिल्ली की जन-जन तक इसको पहुंचाया जा सके।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केन्द्र के 11 साल और दिल्ली के 100 दिन पूरे हुए हैं और जिस प्रकार से दिल्ली में लगातार डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, वह सबको दिखाई दे रहा है। मुझे दुख इस बात की है कि पिछली सरकार केन्द्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को क्रेडिट तक नहीं देती थी। उन्होंने कहा कि 1,25,000 करोड़ का रोडवेज के नाम पर दिया गया, इसके अलावा लैंडफिल साइड पर केन्द्र द्वारा मदद की।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में डबल गति के साथ विकास होने जा रहा है और जो भी टारगेट हमने लिए हैं चाहे वह वायु प्रदूषण हो, जल, बिजली, यमुना से लेकर सड़के हो, सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है।

फेस ग्रुप ने दिल्ली की मुख्य मंत्री को 'फेस राष्ट्रीय गौरव अवॉर्ड 2025' के लिए दिया आमंत्रण

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आज फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉ. मुश्ताक़ अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की और उन्हें आगामी फेस राष्ट्रीय गौरव अवॉर्ड 2025 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। यह समारोह 29 जून को आयोजित किया जाएगा और देशभर से प्रतिष्ठित हस्तियों को इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री से हुई इस ख़ास मुलाकात के दौरान जाहिद हुसैन, मुस्तफा गुड्डू और ज़ैनब अंसारी भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहे। सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में हुई इस बातचीत में डॉ. अंसारी ने फेस ग्रुप की कार्यशैली और उद्देश्यों की संक्षिप्त जानकारी देते हुए बताया कि यह संगठन पिछले 25 वर्षों से सक्रिय मीडिया हाउस के रूप में कार्यरत है। ग्रुप के तहत मासिक पत्रिका का प्रकाशन, डिजिटल न्यूज़ चैनल का संचालन, सामाजिक जागरूकता अभियान, और विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक एवं सम्मान समारोहों का आयोजन किया जाता है।

डॉ. अंसारी ने बताया कि 'फेस राष्ट्रीय गौरव अवॉर्ड' कार्यक्रम का उद्देश्य उन व्यक्तियों और संस्थाओं को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना है, जो समाज, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, कला और पत्रकारिता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में 2025 का संस्करण विशेष रूप से भव्य और समर्पित स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, विशिष्ट अतिथि और समाजसेवी शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आमंत्रण स्वीकार करते हुए कार्यक्रम के उद्देश्यों की सराहना की और समाज में सकारात्मक योगदान देने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के इस प्रयास को सराहनीय बताया।

इस मुलाकात के बाद फेस राष्ट्रीय गौरव अवॉर्ड 2025 समारोह अब और अधिक प्रतिष्ठा और प्रभाव के साथ राजधानी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण आयोजन के रूप में उभरता दिख रहा है।

40 डिग्री से नीचे रहेगा पारा, 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; येलो अलर्ट जारी

दिल्ली में सोमवार को मौसम नरम रहा अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने मंगलवार को आंधी और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 111 दर्ज किया गया जो मध्यम श्रेणी में आता है। इस सप्ताह तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। मौसमी उतार चढ़ाव के बीच सोमवार को भी दिल्ली में गर्मी के तेवर नरम ही रहे। कभी आसमान साफ रहा तो कभी बादलों की लुकाछिपी देखने को मिली। बीच-बीच में हवा भी चलती रही। मौसम विभाग की मानें तो इस पूरे सप्ताह ही अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे रहने की संभावना है। मंगलवार को भी आंधी एवं वर्षा का पूर्वानुमान है।

सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री कम 35.0 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री अधिक 29.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हीट इंडेक्स 42 डिग्री रहा। हवा में नमी का स्तर 77 से 60 प्रतिशत दर्ज किया गया। लोधी रोड पर हुई बंदाबांदी छोड़ दें तो जारी पूर्वानुमान और यलो अलर्ट के अनुसार न तो आंधी चली और न ही कहीं वर्षा हुई।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने, बिजली चमकने, 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने और मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। हवा की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 व 27 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट भी जारी किया है।

मध्यम श्रेणी में रहा दिल्ली का एक्यूआई

वायु गुणवत्ता फिलहाल नियंत्रण में ही चल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक सोमवार को लगातार तीसरे दिन दिल्ली का एक्यूआइ 111 दर्ज किया गया। एक दिन पूर्व रविवार को यह 140 रहा था। यानी 24 घंटे के दौरान 29 अंकों की कमी हुई है। इसे मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एनसीआर के शहरों का एक्यूआइ भी कहीं संतोषजनक तो कहीं मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। हाल फिलहाल इसमें वृद्धि होने की संभावना भी नहीं लग रही।

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मंगलवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने, बिजली चमकने, 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवा चलने और मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। हवा की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है। अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 34 व 27 डिग्री रह सकता है। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट भी जारी किया है।

मध्यम श्रेणी में रहा दिल्ली का एक्यूआई

वायु गुणवत्ता फिलहाल नियंत्रण में ही चल रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मुताबिक सोमवार को लगातार तीसरे दिन दिल्ली का एक्यूआइ 111 दर्ज किया गया। एक दिन पूर्व रविवार को यह 140 रहा था। यानी 24 घंटे के दौरान 29 अंकों की कमी हुई है। इसे मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एनसीआर के शहरों का एक्यूआइ भी कहीं संतोषजनक तो कहीं मध्यम श्रेणी में बना हुआ है। हाल फिलहाल इसमें वृद्धि होने की संभावना भी नहीं लग रही।

सीएम रेखा गुप्ता के बयान असंवैधानिक हैं, इससे पूरे पंजाबी और अरोड़ा समाज का अपमान हुआ है- अंकुश नारंग

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा अरोड़ा समाज को लेकर दिए गए आपत्ति जनक बयान पर कड़ा विरोध किया है। एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने सीएम के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान अपमान जनक बयान देने पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता के प्रति अरोड़ा समाज में भारी आक्रोश है। सीएम रेखा गुप्ता को अपना बयान वापस लेकर पूरे पंजाबी और अरोड़ा समाज से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। पंजाबी समाज ने दिल्ली चुनाव में भाजपा को बढ़-चढ़कर वोट दिया और अब सीएम उसी समाज को अपमानित कर रही हैं।

सोमवार को ''आप'' मुख्यालय पर एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रेखा गुप्ता ने जिस तरह से अरोड़ा समाज के बारे में बोला है, वो निंदनीय है। सीएम रेखा गुप्ता को अरोड़ा समाज के बारे में जरा सा भी ज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अपने बयान के लिए अरोड़ा समाज से माफी मांगनी चाहिए। जब यूनाइटेड इंडिया था और भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। उस समय पंजाब और सिंध भाग हुआ करता था। वहां से बहुत सारे लोग आकर दिल्ली में बसे। इनमें से अधिकतर लोग अरोड़ा समाज से हैं।

उन्होंने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता ने असंवैधानिक शब्द का प्रयोग किया है। सीएम रेखा गुपता ने अपने बयान में कहा है कि झाड़ू वाले का जो अरोड़ा है, वो बन नहीं सकता रोड़ा। अरोड़ा सरनेम भी है। यह सरनेम सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वज भी यही सरनेम इस्तेमाल करते थे। अरोड़ा सरनेम को इतने अपमान जनक तरीके से बोलना और पूरे अरोड़ा समाज के उपर टिप्पणी करना, बहुत ही निंदनीय है। आम आदमी पार्टी सीएम रेखा गुप्ता के बयान की कड़ी निंदा करती है। सीएम रेखा गुप्ता बताएं कि क्या उनको ऐसी असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करनी चाहिए थी।

अंकुश नारंग ने कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पंजाबी समाज के लोग रहते हैं। पंजाबी समाज ने बढ़ चढ़कर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया और पंजाबी समाज के वोटों की बदौलत ही आज भाजपा दिल्ली की सत्ता पर काबिज है। लेकिन आज दिल्ली की मुख्यमंत्री पंजाबी समाज के लिए अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करती हैं। आम आदमी पार्टी सीएम के इस बयान की कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि सीएम रेखा गुप्ता से पूरे अरोड़ा समाज से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान एमसीडी के करोलबाग जोन के चेयरमैन पुनीत राय और नेता वरुण राज सिंह भी मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई शिक्षा नीति खारिज, संघवाद को मिला बल, अब वास्तविक विकल्प पर विचार का समय

रामदास प्रीनी शिवनंदन

मुंबईच्या TISS ने निलंबित केलेले

मई 2025 में तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू करने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने का स्वागत किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि वह राज्यों को नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता और केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब नीति का क्रियान्वयन या गैर-क्रियान्वयन नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। लेकिन इस औपचारिक कानूनी प्रतिबंध से परे, ऊपर से निर्धारित 7कर नीचे इस नीति को थोपने और संघीय लोकतंत्र की भावना के बीच राजनीतिक लड़ाई कहीं अधिक गहरी है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राज्य शिक्षा अनुदान और विश्वविद्यालय अनुदान को नई शिक्षा नीति के अनुपालन से जोड़कर फंडिंग को हथियार बना लिया है, जिससे असहमति जताने वाले निकायों को प्रभावी ढंग से मजबूर किया जा रहा है। इसने राज्यपालों को निर्वाचित विश्वविद्यालय निकायों को दरकिनार करने और सार्थक राज्य या परिसर परामर्श के बिना केंद्रीकृत नियामकों को स्थापित करने का अधिकार देकर संस्थागत स्वायत्तता को खत्म कर दिया है। बाध्यकारी जनादेश, कॉर्पोरेट-हिंदुत्व संयोजन के लिए डिज़ाइन किये गये मानकीकृत पाठ्यक्रम, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और लक्ष्य-आधारित प्रदर्शन पर निजी भागीदारी के जरिए संघ विविध क्षेत्रीय और संस्थागत परिदृश्यों पर एक समान नीति का खाका थोप रहा है। समवर्ती सूची में होने के बावजूद, शिक्षा को तेजी से केंद्रीकृत आवेगों के अधीन लाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति इस प्रवृत्ति की शुरुआत नहीं है; यह इसकी सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति है -- जिसे एक चमकदार और एक प्रगतिशील दस्तावेज के रूप में पेश किया गया है, लेकिन जो गहरे अन्तर्विरोधों और बाध्यकारी संभावनाओं को छुपाता है।

शिक्षा को सार्वभौमिक और आधुनिक बनाने के रोडमैप के रूप में तैयार की गई नई शिक्षा नीति, 2020 "बहुविषयकता" और "21वीं सदी के कौशल" पर जोर देती है। लेकिन ये सब शब्द शिक्षा क्षेत्र में केंद्रीकरण, व्यावसायीकरण और सांप्रदायिकता की ओर वास्तविक बदलाव को छुपाते हैं। अपने वैचारिक मूल में, नई शिक्षा नीति शिक्षा के एक ऐसे दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, जो मुक्ति के बारे में कम और नियंत्रण के बारे में अधिक है। नई शिक्षा नीति की मसौदा समिति के तथाकथित 'विशेषज्ञों' ने गर्व से उल्लेख किया कि इस नीति का उद्देश्य बाजार की जरूरतों के अनुरूप कार्यबल तैयार करना है। "रोजगार योग्यता", "अनुशासन" और "लचीलापन" जैसे शब्दों को प्रगतिशील शब्दावली के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन वास्तव में वे एक ऐसे दृष्टिकोण को लागू करने के लिए कठघोड़े के रूप में काम करते हैं, जो छात्रों को कॉर्पोरेट बाजारों के लिए आज्ञाकारी उत्पाद के रूप में तैयार करता है।

नई शिक्षा नीति स्पष्ट रूप से बहुसंख्यक सांस्कृतिक संहिता से जुड़ी हैं, तीन-भाषा सूत्र के माध्यम से हिंदी के लिए इसका जोर है और बाजार तर्क के साथ इसका संरेखण किया गया है। अतः यह विचार कि इसे सभी राज्यों द्वारा "शब्दशः और भावना" में अपनाया जाना चाहिए, भारत के बहुलतावादी संवैधानिक डिजाइन की अनदेखी करना है। इस नीति के विरोध को क्षेत्रीय स्वायत्तता, भाषाई विविधता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लंबे समय से चले आ रहे जोर के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में, भाजपा नेता द्वारा दायर याचिका, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं, को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। एक कानूनी फैसले से कहीं अधिक, इसे हमारे संविधान के एक प्रमुख संघीय सिद्धांत की न्यायिक पुष्टि के रूप में पढ़ा जा सकता है : कि राज्य, संघ की प्रशासनिक उप-इकाइयाँ नहीं हैं, बल्कि स्वायत्त शक्तियों वाली राजनीतिक इकाइयाँ हैं। न्यायालय के इस फैसले को यदि तमिलनाडु राज्य बनाम राज्यपाल टीएन रवि के पहले के फैसले के साथ पढ़ा जाएं, तो यह रेखांकित होता है कि संघवाद महज एक प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में तर्क दिया गया था कि नई शिक्षा नीति को लागू करने से इंकार करके तीनों राज्य स्कूली बच्चों को उनकी शिक्षा के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। लेकिन जांच-पड़ताल के दौरान यह दावा ध्वस्त हो जाता है। अनुच्छेद-131 के तहत तमिलनाडु की चुनौती - जिसमें केंद्र पर गैर-अनुपालन के दंड के रूप में शिक्षा निधि में 2,291 करोड़ रुपये रोकने का आरोप लगाया गया है, ने केंद्र के वास्तविक खेल को उजागर कर दिया है। जब भी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार नई शिक्षा नीति या अन्य मामलों को लोकतांत्रिक तरीके से लागू नहीं कर पाती है, तो वे वित्तीय ब्लैकमेल का सहारा लेते हैं।

जबकि विपक्षी शासित राज्य सरकारों, जैसे कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक और तेलंगाना तथा तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने नई शिक्षा नीति के पक्ष में केंद्र की बयानबाजी के जवाब में अपनी खुद की शिक्षा नीतियों का प्रस्ताव रखा है, ये उसी बाजार-संचालित बहिष्कार के तर्क में फंसी हुई हैं, जो नौटंकी से ज्यादा और कुछ नहीं पेश करती हैं। बहरहाल, केरल एक क्रांतिकारी विकल्प प्रस्तुत करता है : जहां उच्च शिक्षा प्रणाली का सार्वजनिक वित्त पोषण होता है, जहाँ राष्ट्रीय औसत से अधिक नामांकन है, लिंग समानता (1.52 समानता सूचकांक के साथ) भारत में सबसे अधिक है और जहां राज्य, लोकतांत्रिक शासन द्वारा संचालित होता है। यहाँ, सीपीआइ(एम) के नेतृत्व वाली वाम-लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने अपने स्वयं की शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया है, विदेशी अध्ययनों के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए छात्रवृत्ति दी है, उच्च रैंकिंग के राज्य विश्वविद्यालयों का निर्माण किया है, बुनियादी ढाँचे के लिए पर्याप्त वार्षिक निधि आबंटित की है, शैक्षणिक परिषदों में छात्रों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया है और इन कदमों के क्रियान्वयन के जरिए नई शिक्षा नीति का विरोध किया है, जो इस नई नीति के बहिष्कारवादी, विभाजनकारी मूल्यों पर कोड़ा मारने जैसा है। केरल सार्वजनिक स्कूली शिक्षा के अपने बचाव में आगे खड़ा है। व्यावहारिकता के नाम पर स्कूलों को बंद करने के बजाय हजारों सरकारी स्कूलों को मजबूत किया गया है ; धर्मनिरपेक्ष विषय वस्तु और स्थानीय रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम लगातार अपडेट किए जाते हैं। नई शिक्षा नीति के निजीकरण के एजेंडे की नकल करने से राज्य के इनकार के कारण सरकारी स्कूलों में नामांकन में वृद्धि हुई है और शैक्षिक निर्णय लेने की प्रकिया में समुदाय की भागीदारी मजबूत हुई है।

नई शिक्षा नीति के खिलाफ लड़ाई कानूनी या राजनीतिक रूप से खत्म नहीं हुई है। प्रगतिशील छात्र आंदोलन, खासकर एसएफआई, भारत में नई शिक्षा नीति के खिलाफ प्रतिरोध आंदोलन को बढ़ा रहा है। नई शिक्षा नीति को खारिज करने वाले कैंपस जनमत संग्रह से लेकर इसके बहिष्कारवादी डिजाइन के खिलाफ देशव्यापी विरोध आंदोलन संगठित करने तक, छात्रों ने इस नीति की अलोकतांत्रिक जड़ों को उजागर किया है और केंद्र सरकार के "कोई विरोध नहीं" के दावे को सीधी चुनौती दी है । इसलिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान में उल्लेखित संघवाद को कायम रखने के लिए सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं है ; यह विकल्पों को बढ़ाने का भी निमंत्रण है। शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने में केरल की सफलता प्रतिरोध के लिए एक मॉडल पेश करती है। नई शिक्षा नीति और इसके क्लोन इसमें में सुधार की भाषा बोल सकते हैं, लेकिन इसका व्याकरण सत्तावादी और सांप्रदायिक है। अब संघर्ष वास्तविक जन-केंद्रित विकल्प को संघ परिवार के शोर से ऊपर सुनाने का है।

(लेखक स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) की केंद्रीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं।)

भारतीय जाटव समाज 'राजस्थान इकाई' ने किया मेधावी विद्यार्थियों की प्रतिभा का सम्मान

- चंचल और दीपिका ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में रहकर कीर्तिमान रचा और उनकी सफलता समूचे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत - उपेंद्र सिंह
- जाटब समाज की मेधावी बेटियों — चंचल जिन्होंने 600 में से 599 अंक अर्जित कर राज्य भर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तथा दीपिका, जिन्होंने 600 में से 598 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान हासिल कियाः

परिवहन विशेष न्यूज

दौसा-आगरा, संजय सागर सिंह। भारतीय जाटव समाज की राजस्थान इकाई की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक एवं मेधावी विद्यार्थियों के प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन आज दौसा जिले के महुआ कस्बे में उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस गौरवपूर्ण अवसर पर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह ने विशेष रूप से सहभागिता करते हुए समाज की दिशा और दशा पर सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए और समाज के शैक्षणिक उत्थान व संगठनात्मक सुदृढ़ता पर बल दिया।

समारोह की सबसे प्रेरणादायक झलक वह क्षण रहा जब आर्थिक संसाधनों की सीमाओं को चुनौती देती हुई समाज की दो प्रतिभाशाली बेटियाँ — कु. चंचल मेहरा, जिन्होंने हाईस्कूल परीक्षा में 600 में से 599 अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तथा कु. दीपिका, जिन्होंने 600 में से 598 अंक अर्जित कर दूसरा स्थान प्राप्त किया।

इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र सिंह ने कहा कि चंचल और दीपिका दोनों ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में रहकर यह कीर्तिमान रचा है, और उनकी सफलता समूचे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इन बेटियों ने यह सिद्ध कर दिया कि लगन, परिश्रम और आत्मविश्वास के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। यह आयोजन न केवल सम्मान का अवसर हैं, बल्कि यह सामाजिक चेतना, सामूहिक प्रगति और नई पीढ़ी के आत्मविकास का उद्घोष भी सिद्ध हुआ। समाज के इस आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा न तो संसाधनों की मोहताज होती है, न ही अवसर की, वह सिर्फ संकल्प और संघर्ष से जन्म लेती है। यह समारोह न केवल सम्मान का प्रतीक था, बल्कि यह संपूर्ण समाज के लिए एक संदेश भी हैं, कि शिक्षा ही वह प्रकाश है, जो आने वाले कल को आलोकित कर सकती है।

इस कार्यक्रम में नीट परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले एक दर्जन से अधिक विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया, साथ ही, उनकी उपलब्धियों को नमन करते हुए उनके माता-पिता को भी विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मान प्रदान किया गया। यह समाज की ओर से उनके संघर्ष और समर्पण के प्रति श्रद्धा-सुमन हैं और समाज के प्रति उनके योगदान और त्याग को एक विनम्र अभिव्यक्ति हैं।

इस अवसर पर समाज की प्रेरणा स्रोत हस्तियाँ जैसे कि नत्थी सिंह जसोरा (पूर्व पुलिस अधीक्षक), डॉ. मनमोहन सिंह (MS, MCh), प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान ठेकेदार, लायक सिंह (प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नरी आगरा), अनिल जाटव का उल्लेखनीय योगदान रहा। इन सभी ने मंच से अपने संबोधन में शिक्षा को समाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम बताया और युवाओं से आत्मविश्वास, अनुशासन और परिश्रम की राह पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। इन सभी ने समाज के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में अपने विचारों और अनुभवों से कार्यक्रम को समृद्ध किया।

इस दौरान कार्यक्रम में सेकड़ों गणमान्यजन एवं समाजसेवी उपस्थित रहे।

सतत विकास की बड़ी चुनौतियों में से एक है मरूस्थलीकरण की चुनौती (17 जून दिवस विशेष आलेख)

17 जून को हर साल 'मरूस्थलीकरण एवं अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अन्तर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाया जाता है। विभिन्न मानवीय गतिविधियों जैसे कि वनों की अंधाधुंध कटाई, अत्यधिक चराई, जगह जगह कंक्रीट की दीवारों के खड़े होने(निर्माण कार्यों के कारण), तीव्र औधौगिकीकरण, शहरीकरण के कारण चरागाहों व सिंचित भूमि की कमी, और जलवायु परिवर्तन के कारण आज संपूर्ण विश्व भूमि क्षरण का सामना कर रहा है और सूखा(मरूस्थलीकरण)एक बड़ी समस्या होती चली जा रही है। आज मरूस्थलीकरण के कारण भूमि अपना उपजाऊपन खो रही है और लगातार बंजर भूमि में बदलती चली जा रही है,जो मानवता के लिए एक बड़ा और गंभीर खतरा है। मरूस्थलीकरण या भूमि क्षरण सामाजिक आर्थिक असमानता को जन्म देती है। संक्षेप में कहें तो मरुस्थलीकरण भूमि, जल, जैव विविधता और मानव जीवन को प्रभावित करता है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि 17 जून का दिन वैश्विक स्तर पर लोगों में मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इनसे निपटने के लिए उपायों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है और पहली बार यह दिवस 1995 में मनाया गया था। दरअसल, वर्ष 1992 के रियो पृथ्वी सम्मलेन के दौरान जलवायु परिवर्तन और जैवविविधता के नुकसान के साथ मरुस्थलीकरण को सततविकास के लिये सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में पहचाना गया था और दो साल बाद यानी कि वर्ष 1994 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेज़र्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) की स्थापना की, जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है तथा 17 जून को 'विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस' घोषित किया गया। वास्तव में यह दिवस हमें भूमि के क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे के खतरों से अवगत कराता है।सच तो यह है कि यह दिवस स्थायी भूमि प्रबंधन, पारिस्थितिकीय संतुलन और जलवायु अनुकूलन की दिशा में वैश्विक प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। गौरतलब है कि हर साल इसकी एक थीम या विषय रखा जाता है। पिछले वर्ष 2024 की थीमः 'भूमि के लिए एकजुट। हमारी विरासत। हमारा भविष्य' रखी गई थी जबकि इस वर्ष यानी कि 2025 के लिए इसकी थीम- 'भूमि को पुनःस्थापित करें। अवसरों को खोलें'(रिस्टोर द लैंड, अनलाक द अपोर्चुनीटीज) रखी गई है। बहरहाल, कहना चाहूंगा कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र(इको सिस्टम) और मानवता को बचाने के लिए आज सूखे की स्थितियों अथवा मरूस्थलीकरण से निपटने के लिए एक मजबूत सामुदायिक भागीदारी के साथ ही सभी स्तरों पर सहयोग बहुत ही आवश्यक है, क्यों कि मरूस्थलीकरण से भूमि की उत्पादकता कम होती और जैव-विविधता व धरती की पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत व्यापक असर पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूखे(मरूस्थलीकरण) के कारण धरती पर जल की कमी पड़ती है और इससे धरती के सभी प्राणियों/जीवों, वनस्पतियों और मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आज हमारे देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में सूखे की घटनाओं और अवधि में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि 55 मिलियन आबादी हर साल सूखे के कारण प्रभावित होती है और वर्ष 2050 तक तीन-चौथाई आबादी के प्रभावित होने की आशंका है और 2.3 अरब लोग पहले से ही जल संकट का सामना कर रहे हैं। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा आज के समय में सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों में से हैं, तथा विश्व भर में 40% भूमि क्षेत्र पहले से ही क्षरित माना जाता है। भूमि को स्वस्थ रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है और यदि भूमि स्वस्थ हैं तभी मानव, जीवों व वनस्पतियों का अस्तित्व संभव है। वास्तव में स्वस्थ भूमि ही संपूर्ण विश्व में संपन्न अर्थव्यवस्थाओं का आधार है, और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का आधा से अधिक हिस्सा प्रकृति पर ही निर्भर है, लेकिन यह विडंबना ही है कि आज हम इस प्राकृतिक पूंजी को खतरनाक दर से नष्ट कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हर मिनट, भूमि क्षरण के कारण चार

फुटबॉल मैदानों के बराबर भूमि नष्ट हो जाती है। यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत की कुल भूमि का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से प्रभावित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भारत ने वर्ष 2019 में यूएनसीसीडी कोप-14 सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसमें भूमि बहाली को लेकर कई अहम वैश्विक निर्णय लिए गए थे। यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारत ने वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बहाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बहरहाल, पाठकों को बताता चलूं कि मरूस्थलीकरण से हमारी जैव विविधता का नुकसान होता है, सूखे का खतरा बढ़ता है और इससे समुदाय विस्थापित होते हैं। जल की कमी होती है तो उत्पादन पर व्यापक असर पड़ता है और फसल उत्पादन में अभूतपूर्व कमी आती है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और अस्थिरता और पलायन जन्म लेते हैं। बहरहाल, आज मरूस्थलीकरण रोकने के लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम पर्यावरण संरक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान दें। इसके लिए त्वरित वनीकरण और वृक्षारोपण की आवश्यकता तो है ही, जो वन हैं,उनको बनाए रखने की दिशा में भी हम काम करें। इतना ही नहीं हमें जल प्रबंधन की ओर भी पर्याप्त ध्यान देना होगा और वर्षा जल संरक्षण भी करना होगा।जल उपचारण, जल को व्यर्थ बहने से रोकना,जल का विवेकपूर्ण और पुनः उपयोग, विलवणीकरण या लवणीय पौधों के लिये समुद्री जल का प्रत्यक्ष उपयोग बहुत जरूरी और आवश्यक है। इतना ही नहीं, हमें रेत की बाड़, हवा के झोंकों आदि से होने वाले मृदा क्षरण को भी रोकना होगा। मिट्टी के समृद्ध और अति उर्वरीकरण की आवश्यकता है। वास्तव में सतत भूमि प्रबंधन और जागरूकता बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है।फार्मर मैने नेचुरल रीजेनरेशन (एफएमएनआर), टहनियों की चयनात्मक छँटाई के माध्यम से अंकुरित वृक्षों की वृद्धि को सक्षम बनाता है। पेड़ों की छँटाई से उपलब्ध अवशेषों का उपयोग खेतों को मल्चिंग प्रदान करने के लिये किया जा सकता है, जिससे मिट्टी में पानी की अवधारण क्षमता बढ़ जाती है और वाष्पीकरण कम हो जाता है। वास्तव में हमें संवहनीय कृषि प्रथाओं को अपनाना और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना होगा। यहां पाठकों को बताता चलूं कि संवहनीय कृषि (सस्टेनेबल एग्रीकल्चर) एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो हमारे पर्यावरण, हमारे समाज और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वास्तव में यह प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखती है, और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करती है।वृक्षारोपण, वनों की कटाई रोकना और हरित क्षेत्र बढ़ाना तथा अवैध खनन पर रोक मरूस्थलीकरण रोकने की दिशा में अन्य महत्वपूर्ण कदम हैं। पारंपरिक भूमि उपयोग पर निर्भरता कम करने के लिए गैर-कृषि आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना आवश्यक है। हमें इजराइल की ड्रिप सिंचाई को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। बेहतर सिंचाई विधियाँ, फसल चक्र और नियंत्रित चराई भी मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, सतत विकास और कुशल जल उपयोग को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ महत्वपूर्ण हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय समुदायों की भागीदारी से भूमि सुधार योजनाओं को लागू किया जा सकता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि नीतिगत सहयोग और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देकर मरूस्थलीकरण को रोका जा सकता है।

सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड।

मथुरा में टीला ढह जाने से कई मकान हुए जमींदो कई लोग घायल तीन की मौत

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा। मसानी तिराहा के समीप कच्ची सड़क क्षेत्र स्थित कृष्ण गंगा में सुनील चैन के बाड़े में टीले पर बने कई मकानो के अचानक ढह जाने से हाहाकार मच गया है। सूचना मिलते ही मथुरा के जिला अधिकारी एवं एस एस पी तत्काल मौके पर पहुंच गए। उन्होंने फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस की टीमों के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन एवं राहत बचाव कार्य प्रारंभ कराया और मलबे में दबे एक व्यक्ति को निकाल कर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। मलबे के अंदर दबे हुए लोगों को दमकल विभाग एवं सिविल डिफेंस मथुरा के पोस्ट वार्डन एवं आपदा मित्र अशोक यादव की क्विक रिस्पांस टीम ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से मलवे को हटवाते हुए निकाला गया सूत्र से बताया गया की करीब पांच मंजिल ऊंचे टीले पर कई मकान बने हुए थे। इस जमीन में पार्टनर सुनील चैन निर्माण कार्य करा रहे थे, अचानक रविवार दोपहर टीले के ऊपर बने कई मकान ढह गए। मकानो में कुछ लोग रह रहे थे जो मकान गिरने से मलवे में दब गए। मलबे को हटाने के लिए कई जेसीबी लगाई गई फायर ब्रिगेड एवं सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों एवं नगर निगम एन डी आर एफ, एस डी आर एफ की टीम द्वारा लोगों को मलबे से निकलने का कार्य किया गया। मौके पर जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, नगर निगम आदि विभागों की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। घटना स्थल पर डीएम एसएसपी के अलावा अपर जिलाधिकारी (वित्त राजस्व) पंकज कुमार वर्मा, एवं अन्य पुलिस अधिकारी आदि उपस्थित हैं। सिविल डिफेंस मथुरा के चीफ वार्डन राजीव अग्रवाल डिप्टी चीफ वार्डन कल्याण दास अग्रवाल डिविजनल वार्डन भारत भूषण तिवारी डिप्टी डिविजनल वार्डन राजेश कुमार मित्तल सीनियर स्टाफ ऑफीसर दीपक चतुर्वेदी बैंकर घटना नियंत्रक अधिकारी सचिन अग्रवाल, पोस्ट वार्डन अशोक यादव, राम कुमार चौहान, शैलेश खण्डेलवाल, नितिन सोनी, मुकेश, गोविंद, शैली अग्रवाल, राकेश, राजेश, श्याम बाबू, लड्डू गोपाल, रोहताश, निखिल, राजेंद्र सैनी विवेक आदि वार्डन एवं स्वयंसेवक ने मौके पर जमा भीड़ को नियंत्रण करने में पुलिस प्रशासन के साथ भीड़ को हटाने के लिए काफी मशक्क्त करनी पड़ी है।

सर्राफा कारोबारी से रंगदारी मांगने वालों को जल्द पकड़ने वाली है टीम इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां की गोविंद नगर पुलिस 50 लाख की रंगदारी मामले में फायरिंग करके फरार हुए बदमाशों के नजदीक पहुंच चुकी है जिसके फलस्वरूप पुलिस की परिश्रम पूर्ण सक्रियता उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार करने में भी सफल होगी। पुलिस ने इस घटना के सटीक खुलासे के लिए अब तक अनेक लोगों से गहन पूछताछ भी की है ,जिससे निकले निष्कर्ष के मुताबिक 50 लाख रंगदारी की मांग को लेकर सर्राफा कारोबारी पर फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले अपराधी जल्द ही गिरफ्तार किए जाएंगे। क्योंकि टीम इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह की परिश्रम पूर्ण सक्रियता अब तक बदमाशों की काफी नजदीक पहुंच चुकी है।

यह बात दीगर है कि गोविंद नगर के जुझारू तेवरों वाले इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार सिंह के शिकंजे से बचने के लिए शायद ही कोई ऐसा हथकंडा बचा हो जो इन बदमाशों ने न अपनाया हो लेकिन विभिन्न जनपदों में इसके पहले भी अनेक शातिर अपराधियों को जेल भेजने के साथ ही गोविंद नगर के अपने अब तक के जुझारू कार्यकाल में भी आरोपियों की गिरफ्तारी सहित सभी घटनाओं का सटीक खुलासा करने वाले इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह की अगुवाई वाली गोविंद नगर पुलिस की कठोर परिश्रम पूर्ण सक्रियता का जो परिणाम बहुत जल्द सामने आने वाला है , उसके फलस्वरूप फरार बदमाश बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे।

अवगत कराते चलें कि गत सप्ताह सर्राफा कारोबारी अनिल गुप्ता उर्फ गुड्डू पर बाइक सवार दो बदमाशों ने 50 लाख की गंगा जी की मांग पूरी करने को लेकर गोविंद नगर थाना क्षेत्र में फायरिंग की थी। फायरिंग के तुरंत बाद अज्ञात नंबर से धमकी भरा कॉल आया, जिसमें 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने तत्काल रिपोर्ट दर्जकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी।

जलमग्न हुआ बिनावर बिजली घर क्षेत्र की बिजली सप्लाई ठप

बदायूं। पीछे कई बरसो से चल आ रहा सिलसिला उपखण्ड अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी नहीं लेते मामले को गंभीरता से जिस के चल क्षेत्र में कई दिनों तक पसारता है अंधेरा और करीब 80/100 से अधिक गांवों के लोगों को पानी तथा अन्य जरूरतों के लिए परेशान। अवर अभियंता सतीश चंद्र ने बताया ग्राम पंचायत की तरफ से मानसून से पहले सफाई न होने के चलते ठप हुआ नाला बिजली घर में भरा पूरे क्षेत्र का पानी। जिस के चलते जलमग्न हुआ बिनावर बिजली घर।

न खर्ची न पर्ची ,पूरी पारदर्शिता के साथ बिना रिश्वत व सिफारिश से हुई भर्ती मॉडल को सभी राज्यों ने अपनाना समय की मांग

मेरे सामने 60244 अभ्यर्थी बैठे हैं,उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं कि किसी को भी एक रूपए की रिश्वत नहीं देनी पड़ी है केंद्रीय गृहमंत्रीकी सराहनीय हुंकार को सेल्यूट-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर भ्रष्टाचार रूपी महामारी का डंक पूरी दुनियाँ का हर देश झेल रहा है जिसके उपाय रूपी वैक्सीन का आविष्कार शायद अभी किसी देश ने नहीं किया है,परंतु उपायों पर काम ज़रूर चल रहा है,अगर मन में संकल्प हो,व दिल मेंज़ज्बा लेकर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकना है तो, मेरा मानना है कि डंके की चोट पर सरकारी नौकरियों में न खर्ची न पर्ची, पारदर्शिता के साथ बिना रिश्वत व सिफारिश के साथ भारती करना होगा जिसमें पीएम से लेकर सीएम तक व गृहमंत्री से लेकर अंतिम स्टेज के कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग करना होगा। आज हम इस विषय पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रविवार 15 जून 2025 को मैं देर शाम से टीवी चैनलों इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया से लगातार टच में रहकर यूपी के लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान स्थल पर बड़े पैमाने पर चल रहे 60244 अभ्यर्थियों के जॉइनिंग लेटर सौंपने का समारोह चल रहा था जिसपर मीडिया के माध्यम से मेरी पूरी नजर लगी हुई थी, उसमें माननीय केंद्रीय गृहमंत्री ने दिल को छू लेने वालीबात कही कि यहां 60244 अभ्यर्थी बैठे हैं, हिम्मत से कह रहा हूं कि किसी को भी एक रूपए रिश्वत नहीं देनी पड़ी,बस ! यही बात और यही मॉडल मैं एडवोकेशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र, चाहता हूं कि पूरे देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाए जो, माननीय पीएम और गृहमंत्री ही कर सकते हैं,सेल्यूट सर।चूँकि आज देश के सामने इतनी बढ़ी भर्ती व पारदर्शिता की गारंटी वाली मिसाल कायम हुई है,इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे न खर्ची न पर्ची पारदर्शिता के साथ बिना रिश्वत व सिफारिश से हुई भर्ती मॉडल को सभी राज्यों ने अपनाना समय की मांग है।

साथियों बात अगर हम लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान पर 15 जून 2025 को चल रहे नौकरी जॉइनिंग लेटर सौंपने का समारोह की करें तो,यूपी में 60,244 चयनित सिपाहियों को जॉइनिंग लेटर दिए गए। इनमें से 15 को केंद्रीय गृहमंत्री और सीएम ने लेटर बांटे। बाकियों को समारोह स्थल पर दिए गए। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ, जब इतने बड़े पैमाने पर जॉइनिंग लेटर बांटे गए।चयनित सिपाहियों को 1,300 बसों से लखनऊ लाया गया।गृहमंत्री ने लखनऊ के डिफेंस एक्सपो मैदान में कहा- यूपी सरकार में अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। इस काम को आप सभी 60 हजार युवाओं को और आगे बढ़ाना है। अगले पांच सालों में ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि किसी भी एफआई आर के बाद तीन साल के भीतर उसपर सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा- पहले 11 राज्यों में नक्सलवाद हुआ करता था। पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां कीं। मेरी बात याद रखना, 31 मार्च, 2026 तक भारत नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा।आगे बोले- बिना पर्ची, बिना खर्ची के हुई ये भर्ती रेखांकित करने योग्य है पिछली सरकारों में कई सारी भर्तियां भी हुई,परंतु मेरे सामने 60,244 अभ्यर्थी बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत के साथ कह रहा हूं कि किसी को एक रुपए की रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। भर्ती पारदर्शिता के साथ हुई है। न खर्ची, न पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं, और भ्रष्टाचार से भी नहीं। योग्यता के आधार पर 48 लाख आवेदन में से आपका चयन आपकी योग्यता के आधार पर हुआ है।सिपाही भर्ती में 12 हजार से अधिक बच्चियां हैं, जिनके चेहरे की मुस्कान और तेज देखकर काफी सुकून मिला है। गृहमंत्री ने कहा कि 60,244 युवाओं के लिए आज का दिन शुभ है।चयनित सिपाही बोले- एक भी रुपया घूस नहीं लगा। सीएम ने कहा- याद रखना ट्रेनिंग में जितना पसीना बहेगा, खून उतना कम बहेगा। गरीब से गरीब परिवार का बेटा सिपाही बना है। 8 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने यूपी के युवाओं को साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गईं, चाहे दलित हों, पिछड़े, महिला या पुरुष सबको बिना किसी भेदभाव के भर्ती का अवसर मिला है। उन्होंने अच्छी पुलिस साबित होने का संदेश दिया है।

साथियों बात अगर हम 60244 अभ्यर्थियों के सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया की करें तो,48 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में 150 सवाल पूछे गए थे। हर सवाल के 2 नंबर तय थे, यानें कुल 300 नंबरों की परीक्षा हुई थी। माइनस मार्किंग भी थी,हर गलत सवाल पर 0.25 नंबर काटे गए।सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा के बाद 1,74,316 अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। 10 से 27 फरवरी 2025 के बीचफिजिकल टेस्ट कराया गया,इसके बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर और आरक्षण नियमों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की गई। तीन महीने पहले, यानी 13 मार्च को फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया था।12,048 महिलाओं और 48,196 पुरुषों ने परीक्षा पास की थी। जिसके आधार पर अंतिम रिजल्ट निकला।

साथियों बात अगर हम भ्रष्टाचार के डंक से अर्थव्यवस्था प्रभावित होकर विकास पर असर पड़ने की करें तो,भारत में भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी संस्थानों की अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था को ठप करने के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। 2005 में ट्रान्सपैरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए एक अध्ययन में दर्ज किया गया कि 62 पेर्सेंट से अधिक भारतीयों ने किसी न किसी समय पर नौकरी पाने के लिए एक सार्वजनिक अधिकारी को रिश्वत दी थी। 2008 में, एक अन्य रिपोर्ट ने दिखाया कि लगभग 50 पेर्सेंट भारतीयों को रिश्वत देने या सार्वजनिक कार्यालयों द्वारा सेवाओं को प्राप्त करने के लिए सम्पर्कों का उपयोग करने का प्रत्यक्ष अनुभव था। 2022 में उनके भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ने देश को 180 में से 85वें स्थान पर रखा,इसपैमाने पर जहां सबसे कम रैंक वाले देशों को सबसे ईमानदार सार्वजनिक क्षेत्र माना जाता है। सरकारी समाज कल्याण योजनाओं से धन की हेराफेरी करने वाले अधिकारियों सहित भ्रष्टाचार में विभिन्न कारकों का योगदान है। उदाहरणों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटीअधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान शामिल हैं।भ्रष्टाचार के अन्य क्षेत्रों में भारत का ट्रकिंग उद्योग शामिल है,जो अंतर्राज्यीय राजमार्गों पर कई नियामकों और पुलिस बन्धों को वार्षिक अरबों रुपये की उत्कोच देने के लिए मजबूर है।

साथियों बात अगर हम भारत के महाशक्ति बनने में भ्रष्टाचार भी एक कसौटी होने की करें तो, भारत के महाशक्ति बनने की सम्भावना का आकलन अमरीका एवं चीन की तुलना से किया जा सकता है। महाशक्ति बनने की पहली कसौटी तकनीकी नेतृत्व है। दूसरी कसौटी श्रम के मूल्य की है। महाशक्ति बनने के लिये श्रम का मूल्य कम रहना चाहिये। तब ही देश उपभोक्ता वस्तुओंका सस्ता उत्पादन कर पाता है और दूसरे देशों में उसका उत्पाद प्रवेश पाता है। चीन और भारत इस कसौटी पर अव्वल बैठते हैं जबकि अमरीका पिछड़ रहा है।तीसरी कसौटी शासन के खुलेपन की है। वह देश आगे बढ़ता है जिसके नागरिक खुले वातावरण में उद्यम से जुड़े नये उपाय क्रियान्वित करने के लिए आजाद होते हैं। बेड़ियों में जकड़े हुये अथवा पुलिस की तीखी नजर के साये में शोध, व्यापार अथवा अध्ययन कम ही पनपते हैं। भारत और अमरीका में यह खुलापन उपलब्ध है। चीन इस कसौटी पर पीछे पड़ जाता है। वहां नागरिक की रचनात्मक ऊर्जा पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण है।चौथी कसौटी भ्रष्टाचार की है। सरकार भ्रष्ट हो तो जनता की ऊर्जा भटक जाती है। देश की पूंजी का रिसाव हो जाता है। भ्रष्ट अधिकारी और नेता धन को स्विट्जरलैण्ड भेज देते हैं। ट्रान्सपेरेन्सी इंटरनेशनल' द्वारा बनाई गई सूची में भारत को ८४वां स्थान दिया गया है।पांचवीं कसौटी असमानता की है। गरीब और अमीर के अन्तर के बढ़ने से समाज में वैमनस्य पैदा होता है।सरकारी महकमे से उठी मांग उठ रही है कि भ्रष्टों पर सरकारी भत्ते की मौज हो बंद, तब रिश्वतखोरी के मामले रोकने में कामयाब होंगे।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि न खर्ची न पर्ची,पूरी पारदर्शिता के साथ बिना रिश्वत व सिफारिश से हुई भर्ती मॉडल को सभी राज्यों ने अपनाना समय की मांग। 48 लाख आवेदनों में से 60244 उम्मीदवारों का योग्यता व कौशलता के बल पर चयन का जबरदस्त आगाज़। मेरे सामने 60244 अभ्यर्थी बैठे हैं,उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं कि किसी को भी एक रूपए की रिश्वत नहीं देनी पड़ी है केंद्रीय गृहमंत्रीकी सराहनीय हुंकार को सेल्यूट।

रेनॉल्ट ट्राइबर और किगर फेसलिफ्ट की हो रही टेस्टिंग, लॉन्च से पहले मिली क्या जानकारी, पढ़ें पूरी खबर

परिवहन विशेष न्यूज

आगामी रेनॉल्ट कार लॉन्च रेनो की ओर से भारतीय बाजार में हैचबैक कार से लेकर एसयूवी सेगमेंट तक के वाहनों की बिक्री की जाती है। जानकारी के मुताबिक रेनो की ओर से अपनी एमपीवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी Renault Triber और Kiger के Facelift को लाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में इन दोनों कारों के बारे में क्या जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। फ्रांस की वाहन निर्माता Renault की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्द ही अपनी दो कारों के फेसलिफ्ट वर्जन को लाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Renault Triber और Kiger के फेसलिफ्ट को लेकर क्या जानकारी सामने आई है। इनको कब तक लॉन्च (upcoming Renault car launch) किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Renault Triber और Kiger के Facelift की हो रही तैयारी

रेनो की ओर से ट्राइबर और काइगर के फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों कारों के फेसलिफ्ट को लॉन्च करने से पहले इनकी टेस्टिंग (Renault Triber facelift testing) की जा रही है। टेस्टिंग के दौरान इन कारों को देखा गया है।

क्या मिली जानकारी

टेस्टिंग के दौरान इन दोनों कारों को कई बार देखा (Kiger facelift spy shots) जा चुका है। हाल में देखी गई यूनिट्स को भी पूरी तरह से ढंका गया था। नई यूनिट्स में चौकोर एलईडी टेल लाइट्स, नए बंपर, नई टेल लाइट्स के साथ इनके एक्सटीरियर में कई तरह के बदलावों को नोटिस किया गया है। रेनो काइगर फेसलिफ्ट में बड़ी ग्रिल, एलईडी डीआरएल, फॉग लाइट्स को भी दिया जा सकता है।

इंजन में नहीं होगा बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कारों में सिर्फ कॉस्मैटिक बदलावों को ही किया जाएगा। इनके इंजन में किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद काफी कम है। इनमें मौजूदा एक लीटर इंजन के विकल्पों को ही दिया जाएगा। जिसके साथ मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन के विकल्प दिए जाएंगे। इन कारों को पेट्रोल के साथ ही सीएनजी में भी ऑफर किया जा सकता है।

कब तक होंगी लॉन्च

रेनो की ओर से अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि रेनो की ओर से अगले साल तक इन दोनों कारों के फेसलिफ्ट को पेश किया जा सकता है।

कितनी होगी कीमत

रेनो की ओर से मौजूदा समय में ट्राइबर और काइगर को 6.14 लाख रुपये की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। ऐसे में इन कारों के फेसलिफ्ट की कीमत में ज्यादा बदलाव की उम्मीद कम है। लेकिन कुछ हजार रुपये तक की बढ़ोतरी रेनो की ओर से की जा सकती है।

नोएडा में प्रेमी जोड़े ने किया बाइक पर स्टंट फिर लगा भारी जुर्माना, 53000 के चालान ने उड़ाए होश, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा बाइक स्टंट फाइन आजकल सोशल मीडिया पर लोग कई वीडियो अपलोड करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा करना उनके लिए भी परेशानी का कारण बन जाता है। हाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है। जिसमें प्रेमी जोड़ा बाइक पर स्टंट कर रहा है। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने 53 हजार रुपये का चालान कर दिया है। क्या है पूरा मामला आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। देश में सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। हाल में ही एक यूजर की ओर से वीडियो पोस्ट किया गया है, जो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रेमी जोड़ा बाइक पर स्टंट कर रहा है। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार्रवाई (Noida bike stunt fine) भी की गई है। किस तरह की कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

हाल में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (viral couple stunt video) हो रहा है। जिसमें एक प्रेमी जोड़ा चलती हुई बाइक पर स्टंट कर रहा है। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की गई है।

कहां की है वीडियो

सोशल मीडिया पर जिस वीडियो पर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है वह नोएडा का मामला है। उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए चालान जारी किया गया है।

किन नियमों में जारी हुआ चालान

जानकारी के मुताबिक यह चालान 15 जून 2025 को दोपहर 01.46 मिनट पर जारी किया गया है। जिसमें खतरनाक ड्राइविंग के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 184, आरसी वायलेशन का 39/192 एमवी एक्ट, बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने पर एमवीए का सेक्शन 194डी जैसी कई धाराओं के उल्लंघन पर चालान को जारी किया गया है। यह चालान 53500 रुपये का है।

वायरल हुई वीडियो को तीसरे व्यक्ति ने कार में बैठकर बनाया है। जिसमें कार के आगे एक बाइक चल रही है जिसे चला रहे व्यक्ति के आगे एक लड़की बैठी हुई है। दोनों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है।

वीडियो से प्रभावित न हों

आमतौर पर सोशल मीडिया पर कई तरह की वीडियो को अपलोड किया जाता है। जिससे कई लोग प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन इस तरह की वीडियो से प्रभावित होने की जगह समझदार व्यक्तियों को सबक लेना चाहिए और सड़क पर वाहन चलाते हुए इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए, जिससे न सिर्फ आपकी सुरक्षा को खतरा हो बल्कि अन्य वाहनों की सुरक्षा के लिए आपकी हरकत खतरा बन जाए।

सुरक्षित चलाएं वाहन

सड़क पर कभी भी वाहन चलाएं तो हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए और यातायात के नियमों का पूरी तरह से पालन (traffic rule violation India) करना चाहिए। इससे न सिर्फ आप पुलिस की ओर से होने वाली कार्रवाई से सुरक्षित रह पाएंगे बल्कि आप और अन्य वाहन भी सुरक्षित तरीके से सफर को पूरा कर पाएंगे।

महिंद्रा एक्सयूवी 700 का आ सकता है फेसलिफ्ट वर्जन, पहली बार टेस्टिंग के दौरान नजर आई एसयूवी, जानें क्या होंगे बदलाव

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा XUV700 फेसलिफ्ट भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में एसयूवी की बिक्री करने वाली प्रमुख वाहन निर्माता Mahindra and Mahindra की ओर से Mahindra XUV 700 के Facelift को लाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन को पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस एसयूवी की क्या जानकारी सामने आई है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में एसयूवी सेगमेंट के वाहनों को काफी पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में कई एसयूवी को ऑफर करने वाली प्रमुख वाहन निर्माता Mahindra की ओर से जल्द ही XUV 700 के Facelift को लाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी (Mahindra XUV700 facelift) को लेकर क्या जानकारी सामने आई है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पहली बार नजर आई Mahindra XUV 700 Facelift

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा की ओर से जल्द ही अपनी प्रीमियम एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Mahindra XUV 700 Facelift को लॉन्च किया जा सकता है। निर्माता की ओर से अभी इस बारे में कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इसकी टेसटिंग (XUV700 test mule spotted) की जा रही है।

क्या मिली जानकारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को टेस्ट(upcoming Mahindra SUV) किया जा रहा है। जिस दौरान इसे पहली बार देखा गया है। एसयूवी को वैसे तो पूरी तरह से कवर किया गया था। लेकिन इसकी हेडलाइट्स की जानकारी सामने आ गई है। Mahindra Thar Roxx की तरह ही XUV 700 के Facelift में भी सर्कुलर हेडलाइट्स को दिया जाएगा। इसके साथ ही इसमें नए डिजाइन वाली ग्रिल को भी दिया जाएगा। टेस्टिंग के दौरान देखी गई यूनिट में और किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी फिलहाल नहीं मिली है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें कई नए फीचर्स और इंटीरियर को दिया जा सकता है।

इंजन में होगा बदलाव?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को पहली बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। ऐसे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन उम्मीद है कि इसके इंजन में किसी भी तरह के बदलाव को नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा इंजन के विकल्प की तरह ही इंजन को दिया जाएगा।

नाम में हो सकता है बदलाव

महिंद्रा की ओर से अब नई जेनरेशन कारों को नए नाम के साथ ऑफर किया जा रहा है। कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पर पहले Mahindra XUV 300 को ऑफर किया जाता था, जिसका नाम बाद में बदलकर Mahindra XUV 3XO कर दिया गया। ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि इस सीरीज में आने वाली Mahindra XUV 700 का नाम भी बदलकर Mahindra XUV 7X0 किया जा सकता है।

कब तक होगी लॉन्च

महिंद्रा की ओर से अब नई जेनरेशन कारों को नए नाम के साथ ऑफर किया जा रहा है। कॉम्पैक्ट एसयूवी के तौर पर पहले Mahindra XUV 300 को ऑफर किया जाता था, जिसका नाम बाद में बदलकर Mahindra XUV 3XO कर दिया गया। ऐसे ही उम्मीद की जा रही है कि इस सीरीज में आने वाली Mahindra XUV 700 का नाम भी बदलकर Mahindra XUV 7X0 किया जा सकता है।

कब तक होगी लॉन्च

निर्माता की ओर से अभी इस एसूयवी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि एक बार टेस्टिंग पूरी होने के बाद ही इसे औपचारिक तौर पर पेश किया जा सकता है। ऐसे में इसे साल के आखिर या अगले साल के शुरू में पेश किया जा सकता है।

स्कोडा की इस एसयूवी को मिल सकती है सीएनजी, कंपनी कर रही तैयारी, जानें कब तक हो सकती है लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

आगामी स्कोडा सीएनजी एसयूवी यूरोप की वाहन निर्माताओं में शामिल Skoda की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कोडा की ओर से अपनी एक एसयूवी को सीएनजी तकनीक के साथ लॉन्च किया जा सकता है। किस एसयूवी में सीएनजी को दिया जा सकता है। कब तक इसे सीएनजी के साथ लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। चेक रिपब्लिक की वाहन निर्माता Skoda की ओर से भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी से लेकर प्रीमियम सेडान तक को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता की ओर से जल्द ही अपनी पहली कार में सीएनजी को दिया जा सकता है। किस एसयूवी में सीएनजी को ऑफर (upcoming Skoda CNG SUV) किया जा सकता है। इसे कब तक लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

सीएनजी के साथ आ सकती है स्कोडा की पहली गाड़ी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कोडा की ओर से जल्द ही अपनी एक गाड़ी को सीएनजी के साथ लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निर्माता की ओर से Skoda Kylaq को पहली बार सीएनजी के साथ लॉन्च (Skoda CNG launch plan) किया जा सकता है।

क्या मिली जानकारी

रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता अभी अपनी कारों में सीएनजी को ऑफर करने के बारे में विचार कर रही है। स्कोडा इंडिया के ब्रॉन्ड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा कि यह एक दिलचस्प प्रस्ताव है और इस पर निश्चित रूप से विचार किया जा रहा है। अभी निर्माता जो मूल्यांकन कर रही है उसमें टर्बो इंजन के साथ सीएनजी की अनुकूलता है।

टर्बो इंजन के साथ मुश्किल होता है सीएनजी का विकल्प

देश में अभी तक जिस भी गाड़ी में सीएनजी को ऑफर किया जाता है उसमें सिर्फ नेचुरल एस्पिरेटिड इंजन का ही विकल्प दिया जाता है। ऐसे में स्कोडा की ओर से भी अपनी एसयूवी को टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ सीएनजी को देने में समय लग सकता है।

कितना दमदार इंजन

स्कोडा की ओर से काइलैक को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेडान सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी में एक लीटर की क्षमता का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है। इस इंजन से एसयूवी को 115 पीएस की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ छह स्पीड मैनुअल और छह स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प को भी दिया जाता है।

बिक्री पर हो सकता है असर

स्कोडा की ओर से काइलैक को कॉम्पैक्ट एसयूवी सेडान सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस गाड़ी में एक लीटर की क्षमता का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाता है। इस इंजन से एसयूवी को 115 पीएस की पावर और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ छह स्पीड मैनुअल और छह स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प को भी दिया जाता है।

बिक्री पर हो सकता है असर

निश्चित तौर पर अगर स्कोडा की ओर से काइलैक एसयूवी को सीएनजी के साथ भी ऑफर किया जाएगा तो इसका सीधा असर निर्माता की बिक्री पर हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में डीजल के मुकाबले सीएनजी के साथ कारों की ज्यादा बिक्री हुई है। ऐसे में अगर स्कोडा की ओर से भी इस विकल्प को दिया जाता है तो उसकी कारों की भी मांग में बढ़ोतरी होगी।

सिट्रोन सी3 स्पोर्ट्स एडिशन भारतीय बाजार में लॉन्च, मिले कई बेहतरीन फीचर्स, जानें कितनी है कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

सिट्रॉएन की ओर से भारतीय बाजार में कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक हैचबैक कार Citroen C3 को Sports Edition के साथ लॉन्च कर दिया गया है। Citroen C3 Sports Edition में किस तरह की खासियतों को दिया जा रहा है। इसे किस कीमत पर खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। फ्रांस की वाहन निर्माता सिट्रॉएन की ओर से हैचबैक से लेकर एसयूवी सेगमेंट में कई वाहनों की बिक्री की जाती है। सिट्रॉएन की ओर से ऑफर की जाने वाली Citroen C3 Sports Edition को लॉन्च कर दिया गया है। इस एडिशन में किस तरह के बदलाव किए गए हैं। किस कीमत पर इसे लॉन्च किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Citroen C3 Sports Edition लॉन्च हुआ

सिट्रॉएन की ओर से सी3 हैचबैक कार के स्पोर्ट्स एडिशन को भारतीय बाजार में लॉन्च (Citroen India launch) कर दिया गया है। नए एडिशन में कई कॉस्मैटिक बदलाव किए गए हैं, लेकिन इसके इंजन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

क्या है खासियत

सिट्रॉएन सी3 के स्पोर्ट्स एडिशन में स्पोर्टी डीकल, एंबिएंट लाइट्स और स्पोर्टी पैडल्स को दिया गया है। इसके साथ ही इसके स्पोर्ट्स एडिशन में एक्सटीरियर और इंटीरियर में भी कई खासियतों को दिया गया है। कार में स्पोर्टी पैडल किट, कस्टम स्पोर्ट थीम सीट कवर, मैचिंग कार्पेट मैट, सीट बेल्ट कुशन दिए गए हैं। वहीं इस कार में ऑप्शनल वायरलेस चार्जर और डैश कैम को भी लगवाया जा सकता है।

कितना दमदार इंजन

जानकारी के मुताबिक स्पोर्ट्स एडिशन में सिर्फ कॉस्मैटिक बदलाव ही किए गए हैं। इसके इंजन में किसी भी तरह के बदलाव को नहीं किया गया है। इसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा रहा है। जिससे 108.6 बीएचपी की पावर और 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा। इसके साथ छह स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को दिया गया है।

कितनी है कीमत

Citroen C3 Sports Edition में कई नए फीचर्स को जोड़ा गया है। जिससे इसकी कीमत (Citroen C3 price) में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इसकी मौजूदा कीमत में करीब 21 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी नए एडिशन में की गई है। इसके अलावा डैशकैम और वायरलेस चार्जर के लिए अतिरिक्त 15 हजार रुपये देने होंगे। मौजूदा समय में सिट्रॉएन सी3 की एक्स शोरूम कीमत 6.23 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके टॉप वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 10.19 लाख रुपये है।

किनसे होगा मुकाबला

सिट्रॉएन की ओर से सी3 को हैचबैक कार के तौर पर ऑफर किया जाता है। इस कार का बाजार में सीधा मुकाबला Maruti Wagon R, Maruti Swift जैसी हैचबैक कारों के साथ तो होता ही है। साथ ही इसे सब फोर मीटर एसयूवी के तौर पर ऑफर की जाने वाली Tata Punch, Nissan Magnite, Renault Kiger जैसी एसयूवी के साथ भी होता है।

परिवार व समाज से अपेक्षित भावनात्मक समर्थन न मिल पाने पर भी अक्सर युवा मादक द्रव्यों की ओर आकर्षित होने लगते हैं

विजय गर्ग

नशों का निरंतर बढ़ता प्रचलन देश भर के लिए चिंतनीय मुद्दा बन चुका है। नशा समाप्ति के हरसंभव प्रयासों के बावजूद कुछ राज्यों में समस्या गंभीर रूप धारण करती जा रही है। पंजाब का नाम भी इसी सूची में सम्मिलित है। बार्डर पार पाकिस्तान से ड्रोन के ज़रिए राज्य तक पहुंच बनाने वाली नशा तस्करी ही पंजाब की एकमात्र चुनौती नहीं; मादक द्रव्यों की इस घुसपैठ में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बड़े पैमाने पर आने वाली साइकोट्रॉपिक ड्रग्स भी शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आकलन करें तो इन दवाओं का नेटवर्क देश में भी बराबर सक्रिय मिलेगा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फ़ोर्स (एएनटीएफ) के एडीजीपी अनुसार, हिमाचल प्रदेश के बद्दी, गुजरात तथा देहरादून से संचालित विस्तृत नेटवर्क पंजाब व निकटवर्ती क्षेत्रों में अपना जाल फैला रहा है, जिसमें बिना लाइसेंस कई दवाइयां बनाने वाले कारख़ानों के साथ कुछ पंजीकृत फार्मा कंपनियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। एडीजीपी के तहत, 1 मार्च से अब तक 25.70 लाख नशे की गोलियां व कैप्सूल बरामद हो चुके हैं, 44 के क़रीब दवा कंपनियां एएनटीएफ के रडार पर हैं।

नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट की एक रिपोर्ट देखें तो देश की कुल जनसंख्या के 10 से 75 साल तक की आयुवर्ग के लगभग 20 प्रतिशत लोग किसी न किसी प्रकार के नशे के अभ्यस्त हैं। महिलाएं भी इसमें अपवाद नहीं। आजकल कम उम्र के बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। अनिद्रा, अवसाद, तनाव आदि रोगों के उपचार में प्रयुक्त होने वाली अनेक दवाओं का प्रयोग नशे के रूप में होना गहन चिंता का विषय बन चुका है। 'ड्रग वॉर डिस्टॉर्शन और वर्डोमीटर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, देश में अवैध दवाओं का धंधा बढ़कर लगभग 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जबकि नियमानुसार, भारत में ऐसी दवाओं का सेवन अथवा इन्हें चिकित्सक की पर्ची के बग़ैर बेचना दोनों ही कानूनन निषेध हैं।

दरअसल, इस मुद्दे ने भारत में 'नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस' अधिनियम 1985 (एनडीपीएस), के बाद प्रमुखता हासिल की। कई भारतीय राज्य उपचारात्मक तथा निवारक उपायों के साथ-साथ नशीली दवाओं के उपयोग एवं दुरुपयोग के दुष्प्रभावों के ख़िलाफ़ जागरूकता फैलाकर इस समस्या का निराकरण करने की कोशिश में लगे हैं। हालांकि, सतही तौर पर देश में इस ख़तरे से निपटने के लिए शायद ही कोई कारग़र नीति संज्ञान में हो! कटु, लेकिन सत्य यही है कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने हेतु राज्य प्राधिकारियों तथा स्थानीय सरकारों की सीमित भूमिका से भारत में मादक पदार्थों के उपयोग में कमी नहीं आ पाई।

नशों के प्रति बढ़ते रुझान में विविध कारक ज़िम्मेदार रहते हैं, जैसे- तनाव, अकेलापन, असफलता आदि। रिश्तों से जुड़ी समस्यायों, निर्धनता, बेरोज़गारी, शैक्षिक तथा मनोरंजक संसाधनों तक सीमित पहुंच के चलते भी मादक द्रव्यों के सेवन की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि कुछ लोग इनसे बचने अथवा निपटने के लिए नशीली दवाओं का सहारा लेने लगते हैं। नशे में संलिप्त किसी पारिवारिक सदस्य की देखा-देखी, सोशल मीडिया, फ़िल्मों अथवा कुसंगति के प्रभाव में भी नशीली दवाओं का सेवन आम देखा गया।

युवाओं में साइकोट्रॉपिक ड्रग्स का चलन बढ़ने में प्रमुख कारण है, मूल्य में कम होने के साथ इनका सहज ही उपलब्ध हो जाना। हालांकि ये दवाएं बिना डॉक्टर की पर्ची के बेचने-ख़रीदने की सख़्त मनाही है, बावजूद इसके अवैध ढंग से बिकने वाली इन दवाओं का नशे के तौर पर इस्तेमाल आजकल व्यापक स्तर पर होने लगा है।

मेडिकल विशेषज्ञों के अनुसार, इन नशे की दवाओं का अनुचित उपयोग करने से मानसिक अवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। हेरोइन व अन्य किस्म के नशों का सेवन करने वाले व्यक्ति अक्सर इन ड्रग्स के आदी पाए जाते हैं। दवा का इस्तेमाल बेशक दर्दनाक भावनाओं जैसे- चिंता, अवसाद, एकाकीपन आदि से निपटने के नाम पर किया जाता है लेकिन नशे के रूप में बेलगाम आदत, वास्तव में समस्यायों को बद से बदतर बना छोड़ती है।

नशीली दवाएं ग्रहण करने की लत न केवल व्यसनी का शारीरिक-मानसिक-बौद्धिक स्वास्थ्य बिगाड़ती हैं अपितु पारिवारिक सदस्यों की सामाजिक व आर्थिक क्षमताओं के दृष्टिगत भी प्रतिकूलताएं ही लेकर आती हैं। समूचे समाज तथा सरकार पर अवांछित वित्तीय बोझ बढ़ने लगता है, जिससे शासन-कानून-व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, सभी प्रभावित होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और हानिकारक पदार्थों के निषेध का आह्वान किया गया है। हानिकारक दवाओं का ख़तरा सामाजिक-सांस्कृतिक तथा राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था में गहरी जड़ें जमाए बैठी विकृतियों की अभिव्यक्ति है, अतः इसका समाधान प्रणालीगत, बहुआयामी होना चाहिए। समस्या का निपटान प्रभावशाली ढंग से हो सके, इसके लिए भारत को मज़बूत विनियमन, उन्नत कानून तथा राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही रोकथाम, पुनर्वास तथा सख्त प्रवर्तन पर केंद्रित एक व्यापक राष्ट्रीय नीति भी बाक़ायदा तैयार करनी होगी। परिवार व समाज से अपेक्षित भावनात्मक समर्थन न मिल पाने पर भी अक्सर युवा मादक द्रव्यों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। मैत्रीपूर्ण वातावरण विकसित किया जाए तो यह दुष्वृत्ति काफी हद तक घट सकती है।

जब पढ़ाई में न लगे मन

विजय गर्ग

पढ़ाई एक ऐसा काम है, जिसे करते समय सबसे ज्यादा भटकाव होता है। लेकिन कॉम्पिटिशन के इस माहौल में आप हाथ पर हाथ धर कर भी तो नहीं बैठ सकते। पढ़ाई करते वक्त ध्यान न लगना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टेंशन न लें और दिए गए टिप्स को फॉलो करने की ईमानदार कोशिश करें।

। एक जगह पर रख लें सभी चीजें पढ़ने के लिए बैठने से पहले सारी जरूरी चीजें जैसे कि सब्जेक्ट बुक्स, कॉपी, रफ कॉपी, पेन, पेंसिल आदि अपने पास रख लें। इस तरह आप बार-बार चीजें उठाने के बहाने से उठने से बच जाएंगे। कई बार हमारा दिमाग उस ही तरफ जाता है, जो चीज हमारे पास नहीं होती, इसलिए पूरी तैयारी करके बैठें।

अच्छी नींद लें

हॉर्मोन को सही से रेगुलेट करने के लिए और 1 दिमाग को थकने से बचाने के लिए कम से कम सात घंटे की नींद लें। नींद हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होती है। अच्छी नींद से दिमाग तेज होता है और पढ़ा हुआ याद भी रहता है।

आत्मचिंतन करें

पढ़ाई करते वक्त जब आपका दिमाग इधर-उधर भटकने लगे, तो एक बार खुद से सवाल जरूर पूछें कि इस वक्त का आराम अच्छा है और जिंदगी भर की परेशानी या फिर इस वक्त की लगन और मेहनत के बदले जिंदगी भर का सुकून । इसी चुनाव से आपकी आगे की जिंदगी निर्धारित होगी। RNS EDUCATION

थोड़े से ज्यादा की तरफ बढ़ें

पढ़ाई करने के लिए हमेशा छोटे टाइम पीरियड्स बनाएं। उसके बाद धीरे-धीरे अपना पढ़ने का टाइम बढ़ाते जाएं। इसके लिए एक और ट्रिक है कि जैसे ही आप पढ़ाई से उठने लगें, खुद को एक आखिरी प्रश्न या आखिरी पेज आदि का टारगेट दें। जैसे कि इसे पूरा करने के बाद उठना है बस। इसी तरह धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई का टाइम और लक्ष्य बढ़ाते जाएं।

लक्ष्य होगा, तभी कुछ होगा

यह तय करें कि आपको जिंदगी में करना क्या है? आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हैं, अपने कॅरिअर के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए, पैसे कमाने के लिए या किसी की खुशी के लिए। पढ़ते वक्त अगर मन भागने लगे, तो खुद को अपना लक्ष्य याद दिलाएं। जब आप खुद अपना लक्ष्य तय कर लेंगे, तो कोई भी चीज़ आपको गुमराह नहीं कर सकती।

अपने साथ खुद सख्ती बरतें ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे कि मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, दोस्त- रिश्तेदार आदि से खुद को दूर रखें। आपकी जिंदगी है, कॅरिअर भी आपका है, इसलिए जिम्मेदारी भी सिर्फ आपको ही लेनी होगी। पढ़ाई करते वक्त खुद को समझाएं कि थोड़ी ही देर की बात है और उसके बाद अपने मन की किसी भी चीज के साथ रह सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना तो पड़ेगा ही।

। रेगुलर पढ़ाई से नहीं होगी टेंशन क्या ये मुमकिन है कि आप हफ्ते भर का खाना एक दिन में खा लें? नहीं ना । इसी तरह आप साल भर की पढ़ाई कुछ दिनों में नहीं कर सकते। इसलिए नियमित रूप से पढ़ाई करते रहें। रोज अपने पढ़ने के लिए कुछ घंटे तय करें और उस वक्त पढ़ाई के सिवाय कुछ न करें। इससे परीक्षा के वक्त थोड़े से रिवीजन से भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अपनी जरूरत मुताबिक पढ़ने के लिए सुबह या रात का वक्त तय कर लें। बीच-बीच में छोटे-छोटे ब्रेक्स लेते रहें, ताकि ऊब महसूस न हो।

लवायु संकट और 'इको विलेज'

शहरीकरण और उपभोक्तावाद की बढ़ती संस्कृति ने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। आधुनिक जीवनशैली की यह होड़ हमारे पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव छोड़ रही है। ऐसे में इको- विलेज यानी पारिस्थितिकी गांव एक नए विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, जो टिकाऊ जीवनशैली, आत्मनिर्भरता और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा देते हैं।

दुनिया का पहला इको-विलेज स्काटलैंड के मोरे में 1985 में स्थापित किया गया था। इस इको-विलेज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहां सभी आवश्यक सुविधाएं और सेवाएं केवल 20 मिनट की पैदल या साइकिल की दूरी पर उपलब्ध हैं। इससे लोग निजी वाहनों के प्रयोग से कतराते हैं। एक इको-विलेज पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सामंजस्य और व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देने की भावना पर केंद्रित होता है। ये लोगों को पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। भारत में भी ऐसे कई इको- विलेज हैं, जो पर्यावरणीय स्थिरता और आत्मनिर्भरता दोनों प्रदान करते हैं। राजस्थान का पिपलांत्री, नगालैंड का खोनोमा, तमिलनाडु का आरोविल देश के इको-विलेज के कुछ सफल उदाहरण हैं। पिपलांत्री में बेटी के जन्म पर पौधे लगाने की परंपरा ने गांव को आर्थिक एवं पर्यावरणीय रूप से आत्मनिर्भर बनाया है। इसी तरह नगालैंड स्थित खोनोमा को एशिया का पहला हरित गांव बनने का गौरव हासिल है। जैविक खेती, प्रभावी जल प्रबंधन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देकर यह गांव आज सफल इको- विलेज के रूप में स्थापित हो चुका है। इसी तरह तमिलनाडु का आरोविल गांव जीव-जंतुओं और पेड़- पौधों के प्रति अहिंसा की भावना का विकास कर सह-अस्तित्व कायम करने में जुटा है। इको-विलेज इस अवधारणा पर कार्य करता है कि इंसानी जीवनशैली से पर्यावरण को हानि न हो। यह लोगों को कम कार्बन जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इससे स्थानीय हवा, पानी और मिट्टी की स्वच्छता और शुद्धता कायम रहती है। गांवों को इको-विलेज बनाने की आवश्यकता इसलिए भी अधिक है कि इको-विलेज आत्मनिर्भरता का विकास करने और स्वच्छ पर्यावरण के विकास और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने का अहम माध्यम साबित हो सकते हैं।

आज अधिकांश गांवों ने शहर का स्वरूप ले लिया है। शहरी सुविधाओं की सुलभता ग्रामीण जीवन की सादगी और प्रकृति के साथ जुड़ाव को कहीं पीछे छोड़ दिया है। नतीजतन, पारंपरिक संसाधन-आधारित जीवनशैली, जो कभी पर्यावरण के अनुरूप हुआ करती थी, अब उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों की भेंट चढ़ रही है। ऐसे में इको-विलेज की अवधारणा न केवल एक टिकाऊ विकल्प प्रस्तुत करती है, बल्कि यह हमें हमारी जड़ों से भी जोड़ती है।

आपकी जेब में स्मार्टफोन रूपी 'परजीवी'

विजय गर्ग

आज स्मार्टफोन हमारी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इस छोटे से उपकरण ने हमारे दैनिक जीवन को काफी सुविधाजनक बनाया है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती ! एक हालिया अध्ययन के अनुसार, यह केवल एक मददगार डिवाइस भर नहीं रह गया है, यह एक ऐसे 'परजीवी' का रूप ले चुका है, जो हमारा समय, ध्यान और मानसिक शांति चुपके से चूस लेता है।

स्मार्टफोन के इस दोहरे चरित्र और उसके परजीवी रूप पर दो आस्ट्रेलियाई विज्ञानियों राचेल एल. ब्राउन और राब ब्रूक्स ने 'आस्ट्रेलियन जर्नल आफ फिलासफी' में एक शोधपरक आलेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने यह तर्क दिया है कि स्मार्टफोन समाज के लिए विशिष्ट प्रकार के जोखिम की वजह बनते हैं, जो परजीविता के दृष्टिकोण से देखने पर और भी जाहिर हो जाता है। लेखकों के अनुसार, 'जूं, पिस्सू और टेपवर्म मानव के विकास क्रम में हमारे साथी रहे हैं। फिर भी, आधुनिक युग का सबसे बड़ा परजीवी खून चूसने वाला कोई जीव नहीं है। यह अपनी लत लगाने वाली वस्तु है। इसका मेजबान आज हर इंसान बन चुका है। यह टेक कंपनियों व उनके विज्ञापनदाताओं के हित में है।'

वर्ष 1921 में प्रख्यात विचारक क्रिश्चियन लुइस लैंग ने चेताते हुए कहा था, ₹तकनीक एक उपयोगी नौकर है, लेकिन एक खतरनाक मालिक है।₹ उन्होंने यह बात तब कही थी जब न तो कंप्यूटर आम उपयोग में थे, न ही इंटरनेट की कोई कल्पना की गई थी। आज उनकी यह बात पहले से कहीं अधिक सटीक प्रतीत होती है। आज लैपटाप, टैबलेट और स्मार्टफोन जैसे उपकरण हमारी दिनचर्या में इस तरह घुल-मिल चुके हैं। कि इनसे दूरी बना पाना लगभग असंभव लगता है। हम इनके गुलाम बन गए हैं।

स्क्रीन बार-बार देखे बिना हमें चैन नहीं मिलता। इसका खामियाजा हमें कई रूपों में भुगतना पड़ता है- अनिद्रा, सामाजिक संबंधों की गहराई में कमी और मानसिक स्थिति में चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं उभरना। डिजिटल जुड़ाव ने हमारे असली जीवन से दूरी पैदा कर दी है।

जैसे-जैसे स्मार्टफोन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनते गए, उनमें प्रयुक्त एप्स भी यूजर्स की आवश्यकताओं के बजाय विज्ञापनदाताओं के हितों की सेवा में लगने लगे। इन्हें इस तरह डेवलप किया गया है। कि वे हमारे व्यवहार को प्रभावित करें, हमें लगातार स्क्राल करते रहने, विज्ञापनों पर ध्यान देने और उनमें उलझे रहने के लिए बाध्य करें। यह तकनीकी हस्तक्षेप खुले रूप में नहीं, बल्कि बहुत ही सूक्ष्म ढंग से होता है। हमारा आकर्षण किसी संयोग का नतीजा नहीं होता, बल्कि इसके पीछे एक पूरी प्रणाली काम कर रही होती है जो हमारे व्यवहार का अनुमान लगाकर हमें उसी दिशा में प्रेरित करती है। जरूरत यह समझने की है कि तकनीक हमारे लिए बनी है, हम उसके लिए नहीं।

भारत-अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते की संभावनाएं

ऐसे में 8 जुलाई के पहले अमरीका के साथ किया जाने वाला अंतरिम व्यापारिक समझौता टैरिफ विवादों को सुलझाने और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस संभावित अंतरिम व्यापार समझौते के बारे में जो तस्वीर उभर कर दिखाई दे रही है, इसके तहत अमरीका के बाजार में भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को शून्य करवाने के लिए भारत भी अमरीका की कई वस्तुओं पर शुल्क में राहत दे सकता है'

यकीनन इस समय भारत और अमरीका के बीच अंतरिम कारोबार समझौते के अंतिम दौर की वार्ता इसी माह जून तक पूर्ण किया जाना ट्रंप के बार-बार बदलते टैरिफ रुख के साथ-साथ दो अन्य कारणों से भी भारत के हित में है। कुछ दिनों पहले तक चीन पर भारी टैरिफ लगाने वाले ट्रंप ने अब अमरीका और चीन के बीच व्यापार युद्ध रोककर कारोबारी संबंधों को वापस पटरी पर लाने और दुर्लभ खनिजों पर चीन के निर्यात प्रतिबंधों को हटाने के लिए 11 जून को चीन के साथ करार किया है। इसके तहत जहां चीन अमरीका को मैग्नेट और दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति करेगा, वहीं अमरीका अपने कालेजों और विश्वविद्यालयों में चीनी छात्रों को पढने की अनुमति देगा। इसी तरह अमरीका की व्यापक शुल्क नीति पर अमरीका की संघीय अपील अदालत द्वारा ट्रंप के अनुकूल फैसला दिया गया है। इस फैसले से अमरीका अन्य देशों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए शुल्क का उपयोग कर सकता है। अतएव ऐसे परिदृश्य में भारत और अमरीका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते से ट्रंप के व्यापार यूटर्न पर रोक लग सकेगी। गौरतलब है कि हाल ही में अमरीका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आंतरिक व्यापार समझौता इसी जून महीने में पूरा होते हुए दिखाई दे सकेगा। इस तरह के समझौते को पूर्ण होने में दो या तीन साल लग जाते थे। विगत 29 मई को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मैनहैटन की अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत के द्वारा विभिन्न देशों के विरुद्ध अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी शुल्क सहित अन्य विभिन्न शुल्कों को अवैध ठहराए जाने के बीच अमरीका के साथ भारत की व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ती रहेगी। वस्तुतः इस समय भारत-अमरीका कारोबार के बढने के बारे में तीन बातें रेखांकित हो रही हैं। एक, भारत और अमरीका के बीच 25 जून, 2025 तक एक अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा हो सकती है। दो, भारत सरकार अपनी सरकारी खरीद बाजार का एक हिस्सा विदेशी कंपनियों के लिए खोलने जा रही है तथा इसमें अमरीका की कंपनियां भी शामिल होंगी। भारत सरकार के खरीद अनुबंधों का केवल एक हिस्सा विदेशी कंपनियों के लिए खोला जाएगा। यह हिस्सा मुख्य रूप से केवल केंद्र सरकार की परियोजनाओं से जुड़ा होगा। तीन, अमरीकी कंपनियों के लिए भारत लाभ का बाजार बना हुआ है।

अमरीकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप के द्वारा आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक को अमरीका में बिकने वाले आईफोन भारत में बनाए जाने पर अमरीका में 25 फीसदी टैरिफ लगाए जाने की कड़ी चेतावनी के बाद भी एप्पल ने भारत में आईफोन विस्तार जारी रखने का संकेत दिया है। गौरतलब है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाशिंगटन में अमरीकी वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लटनिक के साथ दोनों देशों के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और कहा कि पारस्परिक लाभ (रेसिप्रोकल) सुनिश्चित करने के लिए वस्तुओं में अंतरिम व्यापार व्यवस्था को आकार दिए जाने की संभावना हैं। अमरीका ने विगत 2 अप्रैल को भारतीय सामान पर अतिरिक्त 26 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था, लेकिन इसे 9 जुलाई तक यानी कुल 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। ऐसे में 8 जुलाई के पहले अमरीका के साथ किया जाने वाला अंतरिम व्यापारिक समझौता टैरिफ विवादों को सुलझाने और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस संभावित अंतरिम व्यापार समझौते के बारे में जो

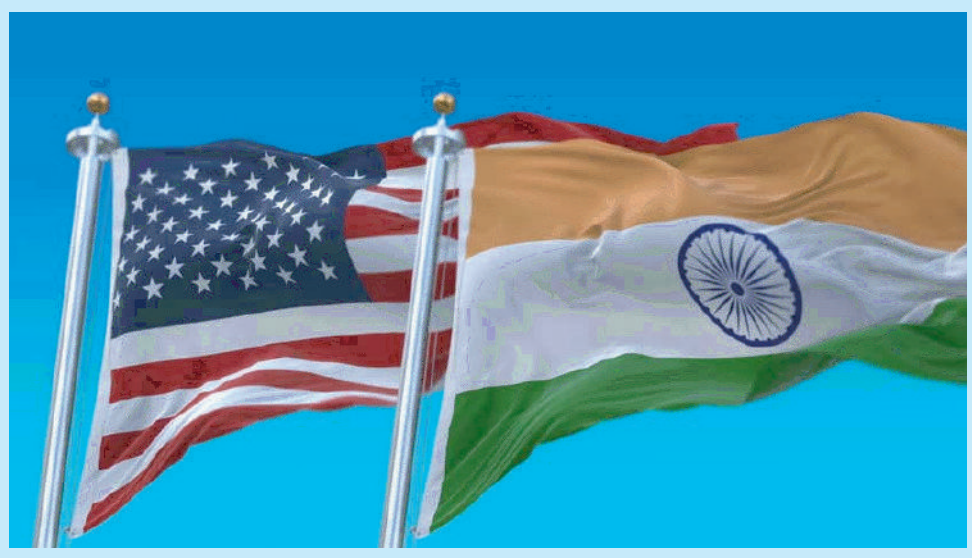

तस्वीर उभर कर दिखाई दे रही है, इसके तहत अमरीका के बाजार में भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को शून्य करवाने के लिए भारत भी अमरीका की कई वस्तुओं पर शुल्क में राहत दे सकता है। अमरीका भारत के बाजार में कृषि उत्पादों का निर्यात करना चाहता है, लेकिन भारत सिर्फ गैर जेनिटिकली मोडिफायड (जीएम) कृषि उत्पादों को ही अपने बाजार में आने की अनुमति देगा। डेयरी जैसे संवेदनशील उत्पादों को भी शुल्क समझौते में शामिल करने की उम्मीद नहीं है। भारत अमरीका से सभी रोजगारपरक सेक्टर में शून्य शुल्क या अति कम शुल्क चाहता है ताकि इन सेक्टर का अमरीका में होने वाला निर्यात बढ़े, जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग व रोजगार बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ, अमरीका इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ, वाइन, एथनाल, कई औद्योगिक आइटम व कुछ खाद्य आइटम के शुल्क में छूट चाहता है। इसके साथ अमरीका भारत के गुणवत्ता नियंत्रण नियम में भी छूट चाहता है। पिछले दिनों अमरीका के वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी वाशिंगटन में एक बैठक में कहा कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसे पहले देश के रूप में सामने है, जिसके साथ अमरीका का द्विपक्षीय-कारोबार समझौता (बीटीए) प्रारंभिक आकार लेने के करीब है। भारत-अमरीका के बीच बीटीए को 31 दिसंबर, 2025 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया गया है।

गौरतलब है कि विगत 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से लेने में अच्छी तरह से कामयाब दिखाई दिए। दोनों देशों ने अमरीका के व्यापार घाटे को कम करने, व्यापार पर गतिरोध के बीच टैरिफ को कम करने, अधिक अमरीकी तेल, गैस और लड़ाकू विमानों की खरीदी के बारे में बात करने और रियायतों पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत और अमरीका के बीच वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के लिए 500 अरब डालर का लक्ष्य निर्धारित किया। साथ ही भारत और अमरीका भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) के निर्माण के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। निश्चित रूप से ट्रंप के द्विपक्षीय व्यापार संबंधी कुछ अपरिपक्व बयानों के बाद भी अब इसी जून माह में अमरीका के साथ शीघ्र ही भारत के अंतरिम व्यापार समझौते और फिर दिसंबर 2025 तक बीटीए से भारत अमरीका कारोबार तेजी से बढ़ते हुए दिखाई देगा। हाल ही में प्रकाशित विदेश व्यापार के नए आंकडों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में अमरीका लगातार चौथी बार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। साथ ही दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यह महत्त्वपूर्ण है कि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में अमरीका को भारत का निर्यात 11.6 प्रतिशत बढक़र 86.51 अरब डॉलर हो गया, जबकि 2023-24 में यह 77.52 अरब डॉलर था। 2024-25 में अमरीका से आयात 7.44 प्रतिशत बढक़र 45.33 अरब डॉलर हो गया, जबकि 2023-24 में यह 42.2 अरब डॉलर था। अमरीका के साथ व्यापार अधिशेष पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में 41.18 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो 2023-24 में 35.32 अरब डॉलर था। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पिछले दिनों ब्रिटेन के साथ हुआ भारत का एफटीए अब अमरीका और यूरोपीय संघ जैसे बड़े देशों के साथ-साथ ओमान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इजरायल, भारत गल्फ कंट्रीज काउंसिल सहित अन्य प्रमुख देशों के साथ भी एक मिसाल के रूप काम कर रहा है। हम उम्मीद करें कि भारत के द्वारा अमरीका के साथ इसी जून माह में संभावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच 2030 तक 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार के लक्ष्य के मद्देनजर मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश से निर्यात बढ़ेंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसरों का निर्माण होगा।

मंत्रिमंडल विस्तार जल्द; 3 मंत्री देंगे इस्तीफा, कई मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: राज्य में भाजपा सरकार ने अपना पहला साल पूरा कर लिया है। बिना मंत्रिमंडल के सरकार अपने शासन का पहला साल पूरा करके अपनी पीठ थपथपा रही है। अब जबकि राज्यव्यापी सरकार अपने पहले साल का जश्न मना रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को ओडिशा आ रहे हैं।इस अवसर पर राज्य सरकार औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री को शासन के पहले वर्ष का रिपोर्ट कार्ड सौंपेगी।

विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री के ओडिशा दौरे के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार रथ यात्रा से पहले होगा या बाहुड़ा यात्रा के बाद। राज्य सरकार के मंत्रियों ने अपना वार्षिक रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। उसके आधार पर मुख्यमंत्री तय करेंगे कि मंत्रिमंडल में कौन अपनी जगह बनाए रखेगा और कौन बाहर होगा। हालांकि इस सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार मोहन सरकार के नए मंत्रिमंडल की रूपरेखा पूरी तरह तैयार हो चुकी है। यह भी तय हो चुका है कि सरकार से किन मंत्रियों को हटाया जाएगा और किसके विभाग बदले जाएंगे। हालांकि सरकार के वर्षगांठ समारोह और प्रधानमंत्री के दौरे के कारण इस संबंध में पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम होगा क्योंकि मंत्रिमंडल में रिक्त 6 पदों के लिए विभिन्न समूहों के 60 नेता दावेदारी कर रहे हैं।

गौरतलब है कि पहली वर्षगांठ के मौके पर कई विभागों के रिपोर्ट कार्ड ने मुख्यमंत्री को संतुष्ट नहीं किया है। अनुभव की कमी, एक मंत्री पर कई विभाग होने से उनके कामकाज पर नकारात्मक असर पड़ा है। इस आधार पर कहा जा रहा है कि आगामी विस्तार के दौरान 2 से 3 मंत्रियों को हटाए जाने की संभावना है और कहा जा रहा है कि कई मंत्रियों को अपने विभाग बदलने पड़ेंगे। इसी तरह, जहां शेष 6 मंत्री पद के दावेदार अपनी-अपनी पैरवी जारी रखे हुए हैं, वहीं तमाम विधायक मंत्री पद की चाहत रख रहे हैं। कई पहली बार विधायक बने लोग भी खुद को इसके लिए योग्य मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकार में मंत्री पद मिला है। इस बीच, पार्टी के अलग-अलग गुटों और बड़े नेताओं के वफादार बताए जाने वाले करीब 20 से अधिक विधायक मंत्री पद पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी तरह, प्रदेश भाजपा के कुछ प्रमुख नेता अपने वफादारों के लिए ओडिशा और दिल्ली दोनों जगह पैरवी जारी रखे हुए हैं। हालांकि, जब दिल्ली नेतृत्व ने यह संकेत दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा भूमिका मुख्यमंत्री की होगी, तो दावेदारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री ने विस्तार के दौरान जहां जिलेवार समानता और पार्टी निष्ठा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, वहीं बताया जा रहा है कि आगामी विस्तार में कई वरिष्ठ नेताओं को निराशा हाथ लग सकती है। इसी तरह मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और युवा चेहरों को समान अवसर देने जा रहे हैं। इसी तरह यह भी चर्चा है कि जिन जिलों से सरकार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हें आगामी विस्तार के दौरान अवसर मिल सकता है। बताया गया है कि इसके बाद मंत्रिमंडल से बाहर किए गए वरिष्ठ नेताओं को निगम-मंडलों और अन्य सरकारी संस्थाओं में नियुक्त कर खुश करने की कोशिश की जाएगी।

"संकीर्ण जीवन-दृष्टि और टूटती नैतिक रीढ़"

"संकीर्ण जीवन-दृष्टि और टूटती नैतिक रीढ़"
"जब जीवन का अर्थ सिर्फ संपत्ति रह जाए"
"अच्छे जीवन की भूलभुलैया: क्या खोया, क्या पाया ?"

आधुनिक समाज में ₹अच्छे जीवन₹ की जो धारणा प्रचलित है, वह दिन-ब-दिन और भी अधिक संकीर्ण, आत्मकेन्द्रित और भौतिकतावादी होती जा रही है। जीवन के उद्देश्य को अब केवल आर्थिक सफलता, सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत सुख तक सीमित कर दिया गया है। इस सोच में मानवीय करुणा, नैतिकता, सामूहिक भलाई और आंतरिक उद्देश्य जैसे तत्वों के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। यह एक ऐसा बदलाव है जो न केवल व्यक्ति की आत्मा को भीतर से खोखला कर रहा है, बल्कि समाज और संस्थाओं के नैतिक ढांचे को भी दिन-प्रतिदिन तोड़ता जा रहा है।

- डॉ0 सत्यवान सौरभ

वर्तमान जीवनशैली में सफलता का पैमाना केवल संपत्ति, आलीशान घर, ब्रांडेड कपड़े और कारों में निहित है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम है, तो उसे अपने समाज में स्वत: ही "सफल" माना जाने लगता है, भले ही उस सफलता के पीछे बेईमानी, छल-कपट, शोषण या नैतिक गिरावट क्यों न हो। यह धारणा कि "साध्य ही सब कुछ है, साधन की परवाह नहीं", अब आम होती जा रही है। इस विचारधारा ने ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, संवेदना और कर्तव्य जैसे नैतिक मूल्यों को बहुत पीछे छोड़ दिया है।

आज का समाज एक ऐसे व्यक्तिवाद का शिकार है जहाँ "मैं" ही प्राथमिक है, "हम" का कोई विशेष महत्व नहीं रहा। यह आत्मकेन्द्रिकता हर क्षेत्र में दिखाई देती है—शहरी नियोजन से लेकर पारिवारिक ढांचे तक। बड़े-बड़े शहरों में सामूहिक स्थानों, खेल मैदानों, पुस्तकालयों और सार्वजनिक चौपालों की संख्या घट रही है। लोग एक-दूसरे से कटते जा रहे हैं, संवाद सीमित होता जा रहा है और सामाजिक जुड़ाव केवल डिजिटल नेटवर्कों तक सिमट कर रह गया है। यहां तक कि त्योहार और पारिवारिक आयोजन भी अब "फोटो-ऑप" बनकर रह गए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर दिखाना होता है, न कि किसी भी प्रकार की वास्तविक आत्मीयता साझा करना।

भौतिकता के इस अंधे दौड़ में तात्कालिक सुख को दीर्घकालिक भलाई पर प्राथमिकता दी जा रही है। संयम, अनुशासन और तप की भावना कमजोर पड़ती जा रही है। सोशल मीडिया, उपभोक्ता वस्तुओं और बाजारवादी प्रचार के ज़रिए यह धारणा पक्की कर दी गई है कि अधिकतम उपभोग ही सुख का पर्याय है। लोग तुरंत मिल रहे संतोष में इतना लिप्त हो चुके हैं कि आत्म-संयम, आत्मनिरीक्षण और दीर्घकालिक दृष्टिकोण जैसी प्रवृत्तियाँ हास्यास्पद प्रतीत होती हैं।

उपभोग के निर्णयों में नैतिकता का कोई स्थान नहीं बचा है। हम जो पहनते हैं, खाते हैं या उपभोग करते हैं—उसके पीछे की कहानी, चाहे वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली हो या किसी मज़दूर के शोषण की, हमें प्रभावित नहीं करती। उदाहरण के लिए, फास्ट फैशन का उद्योग आज भी फल-फूल रहा है, भले ही हम सबको पता है कि इसमें कैसे सस्ते श्रम और पर्यावरणीय संसाधनों का दोहन होता है। नैतिक उपभोक्तावाद आज भी केवल कुछ सीमित वर्गों तक सिमटा हुआ है।

इस सोच का परिणाम है कि समाज में नैतिक मूल्यों का क्षरण तीव्र गति से हो रहा है। लोग अब परिणामों को ही सब कुछ मानते हैं—उस परिणाम की प्राप्ति की प्रक्रिया चाहे जितनी भी अपारदर्शी या अनैतिक क्यों न हो। यह प्रवृत्ति केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट दुनिया, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा, और मीडिया जैसे हर संस्थान में दिखती है। जब लाभ की भूख नैतिक सीमाओं को लांघती है, तब कॉर्पोरेट घोटाले जन्म लेते हैं, नेताओं की ईमानदारी संदेह के घेरे में आती है और शिक्षा की पवित्रता पर व्यापार हावी हो जाता है। नैतिक मूल्यों का ह्रास केवल संस्थागत नहीं है—व्यक्तिगत स्तर पर भी सहानुभूति और करुणा कम होती जा रही है। आज का व्यक्ति अपने लक्ष्य की पूर्ति में इतना डूबा हुआ है कि उसे पड़ोसी की पीड़ा, बुज़ुर्गों की उपेक्षा, या मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रह गया है। यह संवेदनहीनता धीरे-धीरे समाज को ऐसे व्यक्तियों का समूह बना रही है जो साथ रहते हुए भी अकेले हैं, और जिनके बीच आत्मीयता नहीं, केवल उपयोगिता का संबंध रह गया है।

साथ ही, नैतिक सापेक्षवाद का चलन भी बढ़ा है। जो चीज़ें पहले स्पष्ट रूप से सही और गलत मानी जाती थीं, अब उन्हें परिस्थितियों के अनुसार उचित या अनुचित ठहराया जाने लगा है। परीक्षाओं में नकल करना, कार्यस्थलों पर झूठ बोलना, रिश्वत देकर काम करवाना—इन सबको अब "सिस्टम का हिस्सा" मान लिया गया है। यह विचार कि "अगर सब कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं ?" एक सामूहिक नैतिक पतन का संकेत है।

यह सब केवल सामाजिक नहीं, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी खतरनाक है। जब जीवन का उद्देश्य केवल अधिक से अधिक उपभोग बन जाता है, तो संसाधनों का दोहन अपरिहार्य हो जाता है। जलवायु परिवर्तन, जल संकट, जैव विविधता का विनाश—ये सब इसी "अच्छे जीवन" की भ्रामक परिभाषा के दुष्परिणाम हैं। यह विडंबना ही है कि हम एक ऐसा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं जो पृथ्वी के भविष्य को ही अंधकारमय बना रहा है।

आज की स्थिति यह है कि नैतिकता अब केवल ब्रांडिंग का एक उपकरण बन गई है। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ और संस्थाएँ "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व" के नाम पर कुछ घटनात्मक कार्यक्रम करके अपने दामन को उजला दिखाने का प्रयास करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर परिवर्तन नहीं होता। यह "सतही नैतिकता" समाज को धोखा देने के साथ-साथ आत्मप्रवंचना को भी जन्म देती है।

यदि हमें इस गिरावट को रोकना है और एक संतुलित, करुणामय तथा नैतिक समाज की ओर बढ़ना है, तो हमें "अच्छे जीवन" की धारणा को पुनर्परिभाषित करना होगा। जीवन की सफलता को केवल संपत्ति और प्रतिष्ठा से नहीं, बल्कि उद्देश्य, सद्गुणों, सहानुभूति और सामूहिक भलाई से जोड़ना होगा। इस दिशा में कुछ परंपरागत दर्शन—जैसे बौद्ध धर्म, गांधीवाद और जैन दृष्टिकोण—महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। ये परंपराएँ आंतरिक संतुलन, अपरिग्रह, और नैतिक अनुशासन को जीवन की सफलता का आधार मानती हैं।

एक अच्छा जीवन वह है जो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जिया जाए। जिसमें सामुदायिक सहयोग, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और आत्म-संयम हो। जहाँ हम जो उपभोग करें, वह जिम्मेदारी के साथ करें—यह सोचकर कि हमारे निर्णय दूसरों को, प्रकृति को और आने वाली पीढ़ियों को कैसे प्रभावित करेंगे। सरकार द्वारा शुरू किया गया "LiFE" (Lifestyle for Environment) जैसे अभियान इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयास हैं, परंतु इनका प्रभाव तभी होगा जब वे समाज के हर वर्ग तक नैतिक चेतना के साथ पहुँचें।

इस प्रक्रिया में शिक्षा की भी केंद्रीय भूमिका है। नई शिक्षा नीति २०२० ने नैतिक और जीवन कौशल शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात की है, जो एक स्वागतयोग्य कदम है। अगर हम प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को सहानुभूति, कर्तव्य, सच्चाई और न्याय जैसे मूल्यों से परिचित कराएँ, तो एक पीढ़ी तैयार हो सकती है जो "अच्छे जीवन" की एक व्यापक और समावेशी परिभाषा को आत्मसात कर सके। अंतत:, जीवन का अर्थ केवल जीने में नहीं, बल्कि सही ढंग से जीने में है। और सही ढंग से जीना केवल भौतिक सफलता में नहीं, बल्कि एक ऐसे संतुलन में है जहाँ आत्मा शांत हो, समाज स्वस्थ हो और पृथ्वी संरक्षित हो। यदि हम ऐसा जीवन जीना सीखें, तो शायद हम न केवल अपने लिए, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें।

फ्यूजन क्लब 84 गोल्ड के साथ अव्वल, आव्या को मिला सिल्वर

रोलर स्केटिंग में दिखा अनुशासन और उमंग का संगम, ट्रैक बना रंगमंच, बच्चों ने निभाई चैंपियन की भूमिका

परिवहन विशेष न्यूज

बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।प्रदेश में पहली बार राज्य स्तरीय स्पीड रोड स्केटिंग रैंकिंग चैंपियनशिप का सफल आयोजन बिलासपुर के फ्यूजन स्केटिंग क्लब द्वारा रतनपुर रोड स्थित पावर ग्रिड के पास नेशनल हाइवे रेस्ट एरिया में किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से कुल 298 स्केटर्स ने भाग लिया। इसमें साउथ इस्टर्न सेन्ट्रल रेलवे स्कूल की क्लास एक की छात्रा आव्या अग्रवाल ने सिल्वर पदक पर कब्ज़ा जमाया। प्रतियोगिता में खिलाडियों ने न केवल अपनी रफ्तार दिखाई, बल्कि अद्भुत संतुलन और तकनीकी कौशल का भी प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम का उद्घाटन भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस दौरान जेबीसीसीआइ के सदस्य नाथूलाल पांडेय, जनपद सभापति प्रकाश कमलसेन, एचएमएस महामंत्री देवाशीष डे और इंटक अध्यक्ष अनिल दुबे मंचासीन रहे। आयोजन समिति के अध्यक्ष अवधेश विमल और सचिव कान्तानाथ ने हाल ही की अहमदाबाद विमान दुर्घटना में दिवंगत यात्रियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखवाया। प्रतियोगिता के समापन और पदक वितरण समारोह में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, पेंडरवा की सरपंच अंजलि बैगा, खंड चिकित्सा अधिकारी डा. मिथिलेश गुप्ता और प्रो. मनोज कुमार उपस्थित रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाणपत्र प्रदान किए। आयोजन समिति की ओर से डा. मनोज राज ने बताया कि सर्वाधिक पदक फ्यूजन स्केटिंग क्लब बिलासपुर के खिलाड़ियों ने जीते। उन्होंने आयोजन को सफल बनाने में माता-पिता, प्रशिक्षकों, स्वयंसेवकों और क्लब के सभी सदस्यों का विशेष आभार व्यक्त किया। समापन की औपचारिक घोषणा सेवानिवृत्त फौजी हवलदार विभाष चंद्र सरकार ने की। उनके शब्दों में अनुशासन, समर्पण और टीम भावना के बिना किसी भी खेल की सफलता अधूरी है।

दौड़ की शुरुआत नीलेश माडेवार, सीमा पांडेय, कोच फ्रेंकलिन और शीरिन पाल ने हरी झंडी दिखाकर की। प्रतियोगिता में क्वाड और इनलाइन फार्मेट के तहत सात आयु वर्ग बनाए गए थे, जिनमे अंडर-छह से लेकर 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग तक के बालक-बालिकाएं शामिल रहे। हर खिलाड़ी ने दो विभिन्न रेस में भाग लिया। अंत में 84 खिलाड़ियों को स्वर्ण, 84 को रजत और 84 को कांस्य पदक प्रदान किए गए। इसके अलावा टाय रेस और टेनासिटी रेस जैसी

स्पेशल कैटेगरीज में भी बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। इन विशेष वर्गों में भी 12-12 खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक से नवाजा गया।

हरियाणा राज्य के रोजगार कार्यालयों में कार्यरत जाति विशेष के अधिकारियों से जान का खतरा:- नरेश गुणपाल

परिवहन विशेष न्यूज

हिसार। आरटीआई एक्टिविस्ट नरेश गुणपाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा राज्य के अंदर रोजगार कार्यालयों में कार्यरत जाति विशेष के अधिकारी उनसे द्वेषभावना रखते हैं, द्वेषभावना का मुख्य कारण जाति विशेष के उच्च अधिकारियों की काबिलियत एवं उनके हस्ताक्षरों से हुए लाखों रुपयों के घोटालों की पोल खोलना है।

उन्होंने कहा कि जाति विशेष के अधिकारी उन पर इसलिए द्वेषभावना रखते हैं कि उन्होंने जाति विशेष के रोजगार अधिकारियों की फर्जी डिग्री पर नौकरी हासिल करने से लेकर, गबन तक के मामले भी उजागर किए हैं जो कि जाति विशेष के अधिकारी इन्हें बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे हैं तथा उनके खिलाफ झूठे मुकदमे भी इसलिए दर्ज करवाए गए हैं कि झूठे मुकद्धमें दर्ज होने के कारण यह मामला दब जाएगा। और जाति विशेष के रोजगार अधिकारियों की पोल खुलने से बच जाएगी ।

उन्होंने कहा कि वह झूठे मुकदमों से डरने वाले नहीं है अगर रोजगार विभाग के अधिकारी अपनी जगह सही है तो उन पर झूठी एफआईआर दर्ज करवाकर खुद बचने का प्रयास क्यों कर रहे हैं?

रोजगार विभाग हरियाणा के उच्च अधिकारी जाति विशेष के अधिकारियों को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, तथा जांच पूरी होने के बावजूद भी कार्यवाही करने की बजाय लीपापोती कर रहे हैं और दोषी अधिकारियों को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं ।

उन्होंने कहा कि रोजगार विभाग के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय रोजगार विभाग के उच्च अधिकारियों को दोहरी पदोन्नति देकर रोजगार विभाग हरियाणा एवं राज्य सरकार हरियाणा ने यह साबित कर दिया कि वह कितनी विफल है तथा एक फर्जी डिग्री धारक महिला अधिकारी पर कार्रवाई न करते हुए राज्य सरकार की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े होना लाजिमी हैं कि राज्य सरकार कार्रवाई करने की बजाए आंखें मूंदे बैठे हुए हैं ।

उन्होंने कहा कि इस मामले को रोजगार विभाग हरियाणा के उच्च अधिकारियों द्वारा भी दबाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है एक तरफ तो राज्य सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने का ढिंढोरा पीट रही है दूसरी तरफ दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई न करके उन्हें संरक्षण देने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार की असलियत भी जनता के सामने आने लगी है कि वह आम जनता की शिकायतों का कितना निवारण करती है? इससे राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होना लाजिमी हैं कि राज्य सरकार को निष्पक्षता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, ना की दोषी अधिकारियों को संरक्षण देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि डीडीओ के हस्ताक्षरों से 14 लाख रुपए से भी अधिक का घोटाला जिला रोजगार कार्यालय सिरसा में हो चुका है इस बारे में भी राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामले में चुप क्यों है?

गुमला में अंधविश्वास के कारण महिला की हत्या या सनकी ? आरोपी कुंए से गिरफ्तार

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। झारखंड के गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित कमलपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बलिराम खड़िया ने रीना देवी की टांगी से हत्या कर दी। इस घटना से पहले, बलिराम ने जंगल में लकड़ी चुन रही दो महिलाओं, चंद्रमुनी देवी और कोरवाइन, से उनकी टांगी मांगी और उन पर हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गईं। इसके अलावा, उसने एक चार साल के बच्चे अनुज खड़िया को भी डंडे से मारा। सभी घायलों को गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बलिराम ने हमले के बाद एक कुएं में कूदकर आत्मसमर्पण करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे वहां से निकालकर गिरफ्तार कर लिया।

स्थानीय लोगों के अनुसार, बलिराम खड़िया हर्राकरचा गांव का निवासी है। हालांकि, रीना की हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ ग्रामीणों का मानना है कि यह घटना अंधविश्वास से जुड़ी हो सकती है, जबकि अन्य उसकी मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं। घटना के समय, बलिराम ने रीना से पानी मांगा। जब रीना पानी लेकर आई, तो उसने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका के पति अनिल खड़िया तमिलनाडु में मजदूरी करते हैं, और रीना उस समय घर में अकेली थी।

"अदाकार दिलीप कुमार — नाम ही काफी है"

दिलीप कुमार, यानी मोहब्बत, फन और वक़ार का वो दरख़्त, जिसकी छांव में हिंदुस्तानी सिनेमा ने अपनी पहचान पाई।

उनकी अदाकारी में जज़्बातों की वो गहराई थी, जो सीधे दिल तक उतर जाती है।

शख्सियत ऐसी कि हर कोई उनका मुरीद हो जाए — और फन ऐसा, जो वक्त के साथ और भी निखरता चला गया।

असली नामः मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान
जन्म, 11 दिसंबर 1922, पेशावर
रुख़्सत, 7 जुलाई 2021, मुंबई
सफ़र की शुरुआतः 1944, 'ज्वार भाटा' से
पहचानः जज़्बाती और ग़मगीन किरदारों के बेमिसाल अदाकार
दिलीप साहब की खूबियाँ।

अद्भुत अदाकारी, उनके हर किरदार में ज़िंदगी की सच्चाई और एहसास की तासीर मिलती है।

ट्रेजेडी किंग, उनकी ट्रेजेडी फिल्मों (जैसे 'देवदास', 'अंदाज़', 'मुग़ल-ए-आज़म') ने उन्हें यह उपनाम दिलाया।

पुरुस्कार, 8 बार फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर, दादा साहब फाल्के अवॉर्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सब उनकी फनकारी की गवाही हैं।

कुछ यादगार फिल्में,
मुग़ल-ए-आज़म
देवदास
नया दौर
गंगा जमुना
राम और श्याम
अंदाज़

शक्ति

दिलीप कुमार का नाम महज़ एक नाम नहीं, बल्कि हिंदुस्तानी तहज़ीब, मज़हबी हम-आहंगी और फन की बुलंदी की अलामत है।

मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान से 'दिलीप कुमार' बनने का सफर, इस बात की मिसाल है कि फ़न और इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती।

उनकी शख्सियत, उनके किरदार, उनके लफ्ज़ — सब आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं।

दिलीप साहब, आप सिर्फ एक अदाकार नहीं, बल्कि एक दौर, एक तालीम, एक एहसास हैं।

सच में,
दिलीप कुमार, नाम ही काफी है!

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह
सहज, हरदा, मध्य प्रदेश

बदलते समय में माता-पिता की उपेक्षा, कारण और चिंताएँ।

परिवार की संरचना में परिवर्तनः पहले संयुक्त परिवार प्रथा थी, जहाँ कई पीढ़ियाँ साथ रहती थीं। अब एकल परिवार (nuclear family) का चलन बढ़ गया है, जिससे माता-पिता अकेले पड़ जाते हैं।

आर्थिक दबाव, आज की पीढ़ी पर आर्थिक दबाव, करियर की दौड़ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ इतनी हावी हैं कि वे अपने माता-पिता के लिए समय और संसाधन नहीं निकाल पाते।

पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत जीवन की चाहत ने पारिवारिक मूल्यों को पीछे छोड़ दिया है।

संस्कारों का क्षरण, बच्चों को बचपन से ही परिवार, बड़ों के सम्मान और कर्तव्यों के बारे में सिखाना कम हो गया है।

मूल्य शिक्षा की कमी, स्कूल और समाज में नैतिक शिक्षा का अभाव भी एक बड़ा कारण है।

माता-पिता की मनोदशा, भावनात्मक उपेक्षा, माता-पिता को जब अपने बच्चों से अपेक्षित प्रेम, सम्मान और साथ नहीं मिलता, तो वे अंदर से टूटने लगते हैं।

अकेलापन और अवसाद, यह उपेक्षा उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देती है।

क्या युवा अपनी संस्कृति और कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं?

सच्चाई का दूसरा पहलू।

हर युवा ऐसा नहीं है। कई लोग आज भी अपने माता-पिता का आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं।

लेकिन, यह भी सच है कि सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं ने सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को कमजोर किया है।

समाधान और सुझाव,, संस्कारों की पुनर्स्थापना, बच्चों को बचपन से ही माता-पिता के महत्व और कर्तव्यों के बारे में सिखाएँ।

संवाद बढ़ाएँ, परिवार में खुला संवाद और भावनाओं की अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है।

समाज की भूमिका, समाज को भी ऐसे परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए जहाँ माता-पिता उपेक्षित हैं।

माता-पिता का ऋण चुकाना संभव नहीं, लेकिन उनका सम्मान, सेवा और देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। समय चाहे जितना बदल जाए, हमारी संस्कृति की जड़ें इन्हीं मूल्यों में हैं। यदि हम इन्हें भूल गए, तो न केवल परिवार, बल्कि समाज भी कमजोर हो जाएगा।

अपने कर्तव्यों को समझें और माता-पिता को वह स्थान दें, जिसके वे सच्चे हकदार हैं।

माँ-बाप की छाँव,
माँ की ममता, पिता का साया,
इनसे सुंदर जग में क्या पाया।
बचपन की गलियों में थामे हाथ,
उनके बिना सूना है हर एक साथ।
माँ की गोदी, सुख का बिस्तर,
पिता की उँगली, जीवन का सफर।
हर आँधी-तूफान में दी हिम्मत,
हर मुश्किल में बने रहे शक्ति का समंदर।
आज समय की रफ्तार है तेज़,
रिश्तों में आ गई हैं,
कहीं-कहीं खामोशी की सेज़।
फिर भी याद रखो, ये वही दो चेहरे हैं,
जिनकी दुआओं में बसी है तुम्हारी हर खुशी की लहरें हैं।
मत भूलो उनका त्याग, उनकी ममता का रंग,
उनके बिना अधूरा है जीवन का हर संग।
चलो, आज प्रण लें,
माँ-बाप को देंगे वही स्नेह,
जैसा उन्होंने हमें दिया,
हर हाल में, हर उम्र में,
उनकी सेवा में ही सच्चा धर्म है जिया।

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह
सहज, हरदा, मध्य प्रदेश

17 जून: विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस

मरुस्थलीकरण: नीतिगत चूक या जलवायु संकट ?

धरती की छाती पर उभरी गहरी दरारें आज उसकी मूक चीखों का जीवंत प्रमाण हैं। कभी हरे-भरे लहलहाते खेत अब प्यास से सूखकर बंजर हो चले हैं, मानो जीवन की हरियाली उनसे रूठ गई हो। गांव, जो कभी हंसी-खुशी और जीवन की चहल-पहल से गूंजते थे, अब सन्नाटे और खालीपन की गोद में सिमट रहे हैं। मरुस्थलीकरण और सूखा कोई दूर की काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारे पैरों तले धीरे-धीरे पनप रही एक भयावह तबाही है। हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हमें इस संकट की गहराई में झांकने और सचेत होने का कड़ा संदेश देता है। यह दिन केवल जागरूकता का प्रतीक नहीं, बल्कि एक जोरदार पुकार है—धरती को बचाने की, जीवन को संवारने की, और उस हरियाली को लौटाने की, जो हमारी सांसे हैं। यदि हम अब भी नहीं जागे, तो वह भयानक मंजर दूर नहीं, जब उपजाऊ मिट्टी की जगह रेत के अनंत टीले और प्यास की तपिश ही हमारी विरासत बनकर रह जाएंगे।

मरुस्थलीकरण का अर्थ केवल रेगिस्तानों का फैलाव नहीं है। यह उस प्रक्रिया का नाम है, जिसमें उपजाऊ भूमि अपनी उत्पादकता खो देती है। जब खेत बंजर हो जाते हैं, तो सिर्फ फसलें ही नहीं मरतीं, बल्कि उन पर निर्भर समुदायों का सामाजिक और आर्थिक ढांचा भी ढहने लगता है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 40 प्रतिशत से अधिक भूमि मरुस्थलीकरण से प्रभावित है, जो 2.1 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। भारत में यह संकट और भी गंभीर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश की 32.8 प्रतिशत भूमि—लगभग 105 मिलियन हेक्टेयर—मरुस्थलीकरण की चपेट में है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इस खतरे से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अनियंत्रित शहरीकरण, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, रासायनिक खेती, और जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन इस संकट को तेज कर रहे हैं।

विश्व बैंक की 2024 की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि मरुस्थलीकरण के कारण भारत में प्रति वर्ष 2.5 प्रतिशत जीडीपी का नुकसान हो रहा है, जो खेती, आजीविका, और पर्यावरण पर पड़ने वाले दबाव को दर्शाता है।

सूखा इस संकट का सबसे भयावह चेहरा है। जब बारिश अनियमित हो जाती है, जलाशय सूखने लगते हैं, और भूजल स्तर गिरता चला जाता है, तो जीवन का आधार ही डगमगा जाता है। केंद्रीय जल आयोग की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 718 जिलों में से 42 प्रतिशत सूखे की चपेट में हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के आंकड़ों के अनुसार, 2020 से 2024 के बीच सूखे के कारण 68 प्रतिशत कृषि भूमि प्रभावित हुई, जिससे लाखों किसानों की आजीविका छिन गई। सूखे का प्रभाव केवल फसलों तक सीमित नहीं है; यह भूख, बेरोजगारी, और पलायन को जन्म देता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि

संगठन (एफएओ) की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण और सूखे के कारण 1.8 बिलियन लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, और भारत में यह संख्या 20 करोड़ से अधिक है। यह सिर्फ जलवायु परिवर्तन की मार नहीं, बल्कि जल प्रबंधन में हमारी असफलता और नीतिगत कमियों का परिणाम है।

इस संकट से निपटने के लिए भारत सरकार और गैर-सरकारी संगठन कई कदम उठा रहे हैं। 'जल शक्ति अभियान' के तहत 2023 तक 2.5 लाख से अधिक जल संग्रहण संरचनाएं बनाई गईं, जिनमें तालाब, चेक डैम, और कुएं शामिल हैं। 'भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना' के तहत 22 करोड़ से अधिक किसानों को मिट्टी की उर्वरता की जानकारी दी गई है। 'मनरेगा' के जरिए ग्रामीण स्तर पर जल संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत 2024 में 1.2 करोड़ पेड़ लगाए गए। लेकिन इन प्रयासों की सफलता तब तक अधूरी रहेगी, जब तक आम जनता इसमें हिस्सेदार नहीं बनेगी। गांव-गांव में पारंपरिक जल स्रोतों का पुनर्जनन, वर्षा जल संचयन, और जैविक खेती को बढ़ावा देना समय की मांग है। उदाहरण के लिए, राजस्थान के अलवर जिले में 'तरुण भारत संगठन' ने 10,000 से अधिक जोहड़ (पारंपरिक तालाब) बनाकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल स्तर को पुनर्जनन किया है, जिससे 1,000 से अधिक गांवों में खेती फिर से शुरू हुई।

शिक्षा और जागरूकता इस लड़ाई में सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा को शामिल किया गया है, लेकिन इसे और प्रभावी बनाने की जरूरत है। बच्चों को स्थानीय जलवायु संकट से जोड़ना, युवाओं को संरक्षण के लिए प्रेरित करना, और सामुदायिक स्तर पर जिम्मेदारी की भावना जगाना आवश्यक है। विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) की 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति वर्ष एक पेड़ लगाए, तो अगले दशक में 10 बिलियन पेड़ों से मरुस्थलीकरण को 20 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। यह छोटा कदम सामूहिक रूप से बड़े बदलाव ला सकता है।

विकास की अवधारणा को नए सिरे से परिभाषित करना भी जरूरी है। विकास का मतलब केवल सड़कें और इमारतें नहीं, बल्कि टिकाऊ जीवनशैली की ओर बढ़ना है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सीमित और विवेकपूर्ण होना चाहिए। टिकाऊ खेती, नवीकरणीय ऊर्जा, और पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों को अपनाकर हम मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभाव को कम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों ने गुजरात और महाराष्ट्र में जल उपयोग को 40 प्रतिशत तक कम किया है, जिससे फसल उत्पादन में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हमें याद दिलाता है कि धरती हमारी मां है, और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यह केवल नारों या अभियानों का समय नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाने का वक्त है। यदि हमने अब भी आंखें मूंदीं, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। एक बीज बोकर, एक पौधा लगाकर, या जल की एक बूंद बचाकर हम उस क्रांति की शुरुआत कर सकते हैं, जो धरती को फिर से हरा-भरा बनाए। यह लड़ाई हर उस इंसान की है, जो इस नीले ग्रह पर सांस लेता है। संकल्प लें कि हम धरती से सिर्फ लेंगे नहीं, बल्कि उसे लौटाएंगे भी—उसका हरापन, उसका जीवन, और उसकी उम्मीद। क्योंकि धरती के जख्मों को भरना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

सेवायत महारुद्र झा मंदिर परिसर में अन्य श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर : भुवनेश्वर श्री राम मंदिर सेवायत महारुद्र झा मंदिर परिसर में अन्य श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और कार्यरत सरकारी अधिकारियों और सहकर्मियों को अभद्र भाषा में गाली दे रहे हैं। वह मंदिर के अंदर सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं और भक्तों को अच्छे काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनकी वहां अपनी 3 दुकानें हैं और वह दुकान के कर्मचारियों को सरकारी अधिकारियों और सहकर्मियों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यहां कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं किसी भी नियम-कानून का पालन नहीं करूंगा।

एनएच पर 4 ट्रकों की आमने-सामने टक्कर, 3 चालक घायल

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : भुवनेश्वर के पात्रपड़ा आलू गोदाम के पास सीरियल हादसा। कल देर रात 4 ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में 3 ड्राइवर घायल हो गए। सभी घायलों को एम्स में भर्ती कराया गया है। खंडगिरी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।जानकारी के अनुसार, पात्रपड़ा आलू गोदाम के पास सड़क पर एक मिनी ट्रक खराब पड़ा मिला।ट्रक को पहले एक कंटेनर ने टक्कर मारी। दो और ट्रक कंटेनर से टकरा गए। हादसे में तीन ड्राइवर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद खंडगिरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच कर रही है।

चाईबासा में तालाब चोरी !1964 के बाद गायब तालाबों को ढूंढिए : चंदन कुमार , उपायुक्त

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

चाईबासा। झारखंड में हालत ऐसी कि गायब तलाब तलासने सिंहभूम जिला प्रशासन उतरना पड़ा सड़कों पर ,कारण यहां तालाबों की भी चोरी हुई है !ऐसा केवल चाईबासा नहीं वल्कि हर जिले की कहानी है ! इस खोज में पश्चिमी सिंहभूम डीसी के साथ डीडीसी संदीप कुमार मीणा, एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो, जिला खेल पदाधिकारी हर्ष कुमार, सीईओ उपेंद्र कुमार, चाईबासा नगर परिषद की कार्यपालक पदाधिकारी संतोषिनी मुर्मू सहित नगर परिषद के कर्मचारी और अधिकारी इस मुहिम में शामिल शनिवार को शामिल हुए । बताया जाता है कि डीसी 1964 के हिसाब से चाईबासा शहर में 12 तालाबों की खोज करने निकले । लेकिन, अधिकारी उन्हें महज 2 ही तालाब दिखा पाए। अब अन्य तालाबों को खोजने की जिम्मेदारी डीसी ने अधिकारियों को दी है।

तालाब की खोज में निकले डीसी को चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र के रायसेन और जोड़ा तालाब का ही निरीक्षण कर वापस लौटना पड़ा । निरीक्षण के दौरान स्पष्ट दिखा कि 12 तालाबों में 10 तालाबों का वजूद ही खत्म हो गया है। सच तो यह है कि शहरी क्षेत्रों में स्थिति ज्यादा खराब है, तालाब चोरी नहीं हुए हैं, ये लूटे गए हैं। उपायुक्त ने आदेश दिया है कि 1964 के तालाब को ढूंढकर निकाला जाय ।ये हालात हर जिले की है ।

प्लास्टिक, जीवन में धीरे धीरे घुलता जहर, बुझती ज़िंदगी

आज के आधुनिक युग में प्लास्टिक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चाहे पानी की बोतल हो, खाने की पैकिंग, या फिर घर की सजावट—हर जगह प्लास्टिक ने अपनी जगह बना ली है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस प्लास्टिक को हम इतनी आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं, वही धीरे-धीरे हमारे जीवन में ज़हर घोल रहा है?

प्लास्टिक का बढ़ता जहर,

प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है, जो सैकड़ों सालों तक नष्ट नहीं होता। जब हम प्लास्टिक का कचरा फेंकते हैं, तो वह मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करता है। प्लास्टिक के छोटे-छोटे कण (माइक्रोप्लास्टिक) हमारे खाने-पीने की चीज़ों में मिलकर हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। रिसर्च बताती है कि इन माइक्रोप्लास्टिक के कारण कैंसर, हार्मोन असंतुलन, और कई तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं।

हर चीज़ प्लास्टिक की!

आज बाज़ार में मिलने वाली लगभग हर चीज़ में प्लास्टिक है—दूध की थैली, सब्ज़ी का थैला, बच्चों के खिलौने, मोबाइल कवर, फर्नीचर, और यहां तक कि हमारे कपड़ों में भी। यह प्लास्टिक धीरे-धीरे हमारे जीवन में घुलता जा रहा है, और हम अनजाने में इसे स्वीकार कर चुके हैं।

प्लास्टिक के दुष्परिणाम,

प्राकृतिक संसाधनों का नाश, प्लास्टिक कचरे से नदियाँ, समुद्र और ज़मीन प्रदूषित होती है, जिससे जलीय जीव और पशु-पक्षी मर रहे हैं।

मानव स्वास्थ्य पर असर, प्लास्टिक में मौजूद रसायन शरीर में जाकर गंभीर बीमारियाँ पैदा करते हैं।

जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक के उत्पादन और नष्ट करने के दौरान भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसें निकलती हैं।

समाधान, सही कदम बढ़ाने की ज़रूरत।

अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर प्लास्टिक के इस बढ़ते जहर को रोकें। इसके लिए कुछ आसान लेकिन असरदार कदम उठाए जा सकते हैं।

प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, जब भी संभव हो, कपड़े या जूट के थैले का इस्तेमाल करें।

जागरूकता फैलाएँ, अपने परिवार, दोस्तों और समाज में प्लास्टिक के नुकसान के बारे में जागरूक करें।

प्राकृतिक विकल्प अपनाएँ, बांस, कागज, मिट्टी आदि से बनी चीज़ों को प्राथमिकता दें।

सरकार और प्रशासन से सहयोग, प्लास्टिक प्रतिबंध और कड़े कानूनों का समर्थन करें।

प्लास्टिक का बढ़ता जहर हमारे जीवन और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बन चुका है। अगर हम आज सचेत नहीं हुए, तो कल बहुत देर हो जाएगी। आइए, हम सब मिलकर प्लास्टिक-मुक्त समाज की ओर कदम बढ़ाएँ और अपने जीवन को, अपने पर्यावरण को बचाएँ।

रूपरिवर्तन की शुरुआत अपने आपसे होती है, आज ही प्लास्टिक के खिलाफ एक छोटा कदम उठाएँ, कल एक बड़ी क्रांति बन जाएगी !स्वस्थ जीवन के लिए ये कदम महत्वपूर्ण भूमिका साबित होगा। हैं खुद को तो बचाना है, मगर आने वाली नस्लों की सेहत का भी ध्यान रखना होगा।

डॉ. मुश्ताक अहमद शाह सहज हरदा मध्य प्रदेश.

झारखंड में प्रताड़ित पंचायत सेवक द्वारा जहर खाकर मौत के बाद बवाल

बीडीओ सहित तीन पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। झारखंड के गिरिडीह जिला के डुमरी प्रखंड के बीडीओ और मुखिया के पति सहित चार लोगों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कार्यालय परिसर में जहर खाने वाले पंचायत सेवक सुखलाल महतो की मौत पर स्थिति अब असामंजस्य है ।मृतक के शव के साथ रविवार रात से लेकर सोमवार दोपहर तक सैकड़ों लोग प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे रहे ।जहां डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो भी मृतक सुखलाल महतो के परिजनों के लिए न्याय की मांग करते हुए सोमवार धरने पर बैठने के बाद स्थिति रांची तक राजनीति गर्म हो गयी ।

तब आंदोलन कर रहे लोगों की मांगों पर प्रशासन की ओर से सहमति जताए जाने के बाद परिजन शव उठाने तथा धरना समाप्त करने पर राजी हुए। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि सुखलाल महतो ने बीडीओ अन्वेषा ओना सहित जिन चार लोगों के खिलाफ लिखित तौर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी तथा आश्रित को नौकरी दी जायेगी ।

जानकारी के अनुसार सुखलाल महतो डुमरी प्रखंड के बलथरिया ग्राम के पंचायत सेवक के रूप में कार्यरत था। वह इसी प्रखंड के कुलगो गांव के रहने वाले तथा डुमरी की बीडीओ अन्वेषा ओना, बलथरिया पंचायत की मुखिया के पति परमेश्वर नायक और रोजगार सेवक अनिल कुमार पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए क्षेत्र के विधायक के नाम एक पत्र भी लिखा था।

इसके बाद उन्होंने 13 जून को कार्यालय परिसर में ही कीटनाशक खा लिया । रांची स्थित रिम्स में इलाज के दौरान 15 जून को उनकी मौत के बाद लोग उनका शव लेकर सीधे प्रखंड कार्यालय पहुंचे और देर रात से धरने पर बैठ गए।

घटना की जानकारी मिलने के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने 14 जून को ही इस मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की थी, जिसमें अपर समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ, सरिया बगोदर के एसडीएम संतोष कुमार गुप्ता, मुख्यालय डीएसपी नीरज कुमार सिंह एवं डॉ. रवि महर्षि शामिल हैं।

मारवाड़ी युवा मंच पर्ल महिला शाखा सिकंदराबाद द्वारा शाखा के सदस्यों के लिए स्पोर्ट्स रखा गया।

जगदीश सीरवी

सह मंत्री सुमन घोड़ेला द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शाखा की अध्यक्षा शीतल जैन के नेतृत्व में आनंद सब के तहत नेकलेस रोड स्थित संजीवीया पार्क में शाखा की महिलाओं के लिए स्पोर्ट्स रखा गया। इसमें 30 मेंबर ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है । इसमें कई तरह के खेलों का आयोजन रखा गया । जिसमें सभी सदस्यों को बचपन की यादें ताजा हो गई। स्पोर्ट्स कन्वीनर मोना सोनी और उर्मिला ढल्ला ने सभी का तहदिल से आभार व्यक्त किया है।

स्कूल चले हम।

आज से नये मध्य-प्रदेश में स्कूलों का नये सत्र की शुरुआत हो चुकी है

छोटे छोटे बच्चे

निकल रहे अपने घर से स्कूल जाने के लिए।
बस्ता बेग बटल लिए नई रोशनी नये सपने लिए
नये दोस्तों के मिलने वाला एहसास मन में लिये।
कुछ नया कर गुजरने के लिए । शिक्षा के इस
दौर में छोटे छोटे बच्चे स्कूल चले हम ।

प्रेषक - फोटो स्वतंत्र लेखक हरिहर सिंह चौहान

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023